A Daily News Magazine
इंदौर
बुधवार, 10 दिसंबर, 2025
सुबह सवेरे
इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 11 अंक 75, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

04 - क्या इंडिगो संकट किसी नए बदलाव की आहट है?

05 - सुरक्षित बचपन की दिशा में भारत का भविष्य

06 - हमारी दैनिक आवश्यकताएं एवं मानवाधिकार के प्रश्न

07 - सांसद खेल महोत्सव के तहत दौड़, कूद एवं रस्साकसी प्रतियोगिता...

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

अमेरिकी साम्राज्य अब अमेरिकी ड्रीम को ही कुचल रहा है...

डॉ. मुक्तेदर ख़ान

अमेरिका अपनी तारीख़ के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहाँ लिए गए फ़ैसले उसकी तक़दीर तय करेंगे। अगर उसने गलत राह चुन ली तो वह भी ब्रिटेन की तरह हो जाएगा–एक ऐसा मुल्क जो कभी महाशक्ति था, लेकिन आज अपने पुराने वक़ार की परछाई में जी रहा है और जिसकी ताक़त और इज़्ज़त धीरे-धीरे ढल रही है।

लेकिन अगर उसने सही चुनाव किया, तो वह इस दौर की सबसे अहम और ताक़तवर क़ौम बना रह सकता है–अपनी आर्थिक बरक़रारी और सैन्य बढ़त दोनों को बचाए रखते हुए। मगर अगर वह लड़खड़ा गया, उसने गलत रास्ता पकड़ लिया, तो फिर अमेरिका भी उन मुल्कों की कतार में शामिल हो जाएगा जिन्हें हम आज इसलिए नहीं पढ़ते कि उनका आज कोई असर है, बल्कि इसलिए कि उनका उत्थान और पतन इतिहास का हिस्सा है।

1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से अमेरिका तकरीबन तीन-साढ़े तीन दशक तक दुनिया का एकमात्र सुपरपावर रहा है–इतिहास में यह दौर बहुत कम नजर आता है। दुनिया पर इसका असर और दबदबा उस स्तर तक पहुँच गया था जो शायद ऑटोमन सल्तनत के दौर में ही देखा गया था। लेकिन अब चीन के उभार ने इसे चुनौती देनी शुरू कर दी है। कई लोग चीन को पहले ही बराबरी का प्रतिद्वंद्वी समझने लगे हैं, और लगभग सबका मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच ताक़त का फ़ासला बहुत तेजी से कम हो रहा है।

हार्ड पॉवर की बात करें तो अमेरिका आज भी दुनिया का सबसे ताक़तवर मुल्क है। उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया के कुल GDP का 25 फ़ीसद से ज़्यादा है। उसकी फ़ौज भी बेमिसाल है। लेकिन घर के अंदर हालात ठीक नहीं। मुल्क नस्ल, वर्ग और आप्रवासन को लेकर गहरे तौर पर बँटा हुआ है। मगर सबसे बड़ी दरार अमीर और ग़रीब के बीच बढ़ती हुई खाई है।

जनतंत्र की असली ताक़त एक मज़बूत मिडिल क्लास में होती है। ब्रिटेन में लोकतंत्र इसलिए उगा, क्योंकि वहाँ एक नया मिडिल क्लास पैदा हुआ–जिसने दौलत तो कमा ली थी पर जिसके हाथों मे सत्ता नहीं थी। उसकी इसी जद्दोजहद ने ब्रिटेन को लोकतांत्रिक बनाया।

आज अमेरिका में मिडिल क्लास लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, और व्यावहारिक रूप से मुल्क दो हिस्सों में बाँट गया है–एक अमीर अमेरिका जहाँ प्रति व्यक्ति आमदनी $75,000 से ऊपर है, और दूसरा गरीब अमेरिका जहाँ यह $20,000 से भी कम है। यह बढ़ती हुई खाई देश की नैतिक ताक़त को कमजोर कर रही है–वही नैतिक ताक़त जिसने 1945 से लेकर आज तक अमेरिका को दुनिया की रहनुमाई करने लायक बनाया था।

आज अमेरिका में affordability का बड़ा संकट है। ज़्यादातर लोग अच्छा घर नहीं खरीद सकते, हेल्थकेयर नहीं कर सकते और अपने बच्चों की तालीम का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। नौजवान घर खरीदने और परिवार बसाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं।

इन सब वजहों से अमेरिकन ड्रीम आम आदमी की पहुँच से बाहर होता जा रहा है–और साथ ही अमेरिका दुनिया भर में जंगों और टकरावों में उलझा हुआ है: यूरोप में, पूर्वी एशिया में, और मध्य-पूर्व में। वक्त आ गया है कि अमेरिका घर लौटे–पहले अपने लोगों की फिक्र करे। जहाँ गरीब अमेरिका तंगहाली में है, वहीं अमीर अमेरिका दुनिया में दबदबा हासिल करने की कोशिशों में लगा है। अमीर अरबों-खरबों डॉलर, जो राजनीति और नेताओं पर असर डालते हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। अमीर तबका अमरीकी विदेश नीति को अपनी पसंद के मुताबिक मोड़ चुका है। उसके लिए यूक्रेन की सरहदें अमेरिका की अपनी सीमा-सरहदों से ज्यादा अहम हैं; वे 'ग्रेटर इज़राइल' के सपने को आगे बढ़ाने में मदद चाहते हैं; यूरोप को लगातार सब्सिडी और सुरक्षा देना चाहते हैं; और चीन के उभार को रोकने के लिए ताइवान को हथियार बनाना चाहते हैं।

आज अमरीकी समाज–मज़दूर वर्ग और मिडिल क्लास–विदेश नीति के बोझ तले टूट रहा है। देश चार बड़े बोझ ढो रहा है, और अगर इन्हें न उतारा गया, तो इतिहास एक बार फिर यही साबित कर देगा कि साम्राज्य अपनी हद से ज्यादा फैलने के कारण ढह जाते हैं–बाहर की ताक़तों से नहीं, बल्कि अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले।

यूक्रेन अपनी जमीन वापस चाहता है–2022 में खोई हुई और 2014 में ली गई जमीन भी। लेकिन कीमत कौन भर रहा है? अमेरिकी टैक्स देने वाले नागरिक। यूरोप अमन, सुरक्षा और तरक्की चाहता है–लेकिन योगदान बहुत कम देता है। फिर बोझ किस पर? अमेरिकी जनता पर। इज़राइल एक धार्मिक-राष्ट्रीय ख्वाब के पीछे भाग रहा है–'ग्रेटर इज़राइल' की तामीर, फ़िलिस्तीनियों की आज़ादी की ख्वाहिश को कुचलना, और मध्य-पूर्व में हावी होना। और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? एक बार फिर–अमेरिकी टैक्सपेयर।

इज़राइल का मामला तो इतना बढ़ गया है कि अमेरिका अपने ही नागरिकों और अपनी ही यूनिवर्सिटियों के खिलाफ हो गया है–हार्वर्ड और कोलंबिया जैसे इदारों को कमजोर कर रहा है–सिर्फ इसलिए कि कहीं इज़राइल के मंसूबों पर असर न पड़ जाए। आज इज़राइल का बचाव अमेरिका को अंदर से चीर रहा है–डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों के अंदर दरारें पड़ गई हैं। ताइवान आज़ादी का सपना देखता है–लेकिन यह सपना दुनिया को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल सकता है। और फिर खर्च कौन उठाएगा? अमेरिकी जनता।

अमीर अमेरिकियों को विदेश नीति की फिक्र गरीब अमेरिकियों से ज्यादा है। वे अपने लिए टैक्स कटौती मांगते हैं, सरकारी सब्सिडी लेते हैं, बिज़नेस-फ्रेंडली पॉलिसियाँ बनवाते हैं और करोड़ों डॉलर चंदे में देकर नेताओं को खरीद लेते हैं। बदले में ये नेता टैक्सपेयर्स का पैसा विदेश नीति पर उड़ाते हैं–और हेल्थकेयर, तालीम, रिसर्च वगैरह के फंड काट देते हैं। यहाँ तक कि उन यूनिवर्सिटियों पर हमला किया जा रहा है जिन पर कभी अमेरिका की तरक्की टिकी थी।

सीधी बात ये है कि अमेरिका की विदेश नीति अब अपने ही लोगों की खुशहाली के लिए सबसे बड़ी खतरा बन चुकी है। अमेरिकन ड्रीम का सबसे बड़ा दुश्मन, वही विदेश नीति है जो कहती है कि वह उसे बचा रही है। अगर अमेरिका को एक महान मुल्क की तरह क़ायम रहना है, तो उसे बाहर नहीं, अंदर देखने की ज़रूरत है। मक़सद के बिना ताक़त को ज़ंग लग जाती है; और संतुलन के बिना महत्वाकांक्षा तबाही लाती है।

अमेरिकन ड्रीम की बहाली किसी नई जंग से नहीं, बल्कि घर के अंदर नई तामीर से होगी–इंसाफ़ की बहाली से, लोकतंत्र को दोबारा ज़िंदा करने से, और उस वादे पर यक़ीन वापस लाने से जिसने कभी इस मुल्क को उठाया था।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

● पीएम मोदी एनडीए की संसदीय दल की बैठक में बोले

पेपरवर्क खत्म हो, नियम-कानून जिंदगी आसान बनाने के लिए हो

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में मंगलवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) की संसदीय दल की बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री का माला पहनाकर सम्मान किया गया। पीएम ने बैठक में कहा, मैं फालतू पेपरवर्क और 30-40 पेज के फॉर्म का कल्चर खत्म करना चाहता हूं। हमें नागरिकों के दरवाजे पर सर्विस देनी होगी, बार-बार डेटा जमा करने की जरूरत को खत्म करना होगा। पीएम ने इंडिगो संकट पर कहा- लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें असुविधा नहीं होनी चाहिए। नियम और कानून अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए लोगों को परेशान करना सही नहीं है।

बैठक में पीएम ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार जीत के शिल्पकार हैं। बैठक में रक्षा राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव समेत अन्य नेता भी उपस्थित थे।

● राज्यसभा में वंदे मातरम् चर्चा पर गृहमंत्री शाह बोले

वंदे मातरम् का विरोध गांधी परिवार के खून में

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' पर मंगलवार को चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- जो लोग वंदे मातरम् के महत्व को नहीं जानते वे इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। शाह के बयान को प्रियंका गांधी के बयान से जोड़ कर देखा जा रहा है। हालांकि शाह ने प्रियंका का नाम नहीं लिया। शाह ने संबोधन में कहा- जब वंदे मातरम् 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बना दिया गया। वंदे मातरम् का विरोध गांधी परिवार के खून में है।जब 150 साल पर कल सदन (लोकसभा) में चर्चा शुरू हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य (राहुल-प्रियंका) नदारद थे। वंदे मातरम् का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। दरअसल राष्ट्गीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने के मौके पर भारत सरकार की ओर से सालभर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

● लोकसभा में चुनाव सुधार पर राहुल गांधी ने कहा-

वोट चोरी राष्ट्र विरोधी काम, आरएसएस सभी संस्थाओं पर कंट्रोल है चाहता

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधार (एसआईआर) पर 28 मिनट की स्पीच दी। कहा कि आरएसएस और भाजपा देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही हैं। इनमें चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शामिल हैं। इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव आयोग को कंट्रोल और निर्देशित (डायरेक्ट) कर रही है। इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है।

5 बार हुआ हंगामा

राहुल की स्पीच के दौरान 5 बार हंगामा हुआ। हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल के जिक्र के समय कांग्रेस सांसदों द्वारा मॉडल की तस्वीर दिखाने पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। कहा– ऐसे सदन नहीं चलेगा।

3 मांगें रखीं, कहा- ईवीएम देखने दी जाए

- मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से एक महीने पहले दी जानी चाहिए।
- सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला जाना चाहिए।
- चुनाव के बाद ईवीएम देखने के लिए दी जाए। वोट चोरी से बड़ा कोई एंटी नेशनल काम नहीं है। सरकार चुनाव सुधार नहीं चाहती।

शरद की सुबह

बयासी पार की नौका,
यादों की पतवारों,
संस्मरणों के झोंकों से,
ठीक ठाक चल रही है!
किसने सहयोग दिया,
किसने डुबोने की कोशिश की,
किसने हिचकोले खिलाये,
सभी कुछ एकत्र करने को,
हर पल मचल रही है!
जहाँ आग है, ठंडी हो रही,
औऱ बर्फ यदि जमी है,कहीं ,
धीरे धीरे सारी की सारी,
वह भी पिघल रही है!
आत्मा की सरिता,
कहीं भी अवरुद्ध नहीं,
निरंतर प्रवहमान,
कल कल करती हुई,
पता नहीं,क्या आस लिये,
अभी भी चल रही है!

– हरि जोशी

चुनाव आयोग ने दिया निर्देश

तीस दिन के अंदर अपना संविधान जमा करें...

नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों से कहा है कि 30 दिनों के अंदर सभी संशोधनों के साथ अपने-अपने संविधान का अपडेटेड वर्जन उसके पास जमा करें। चुनाव आयोग ने यह निर्देश ऐसे समय में दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन से लेकर उसके संचालन तक को लेकर वैधानिक नियावली बनाने की मांग की गई है, ताकि इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

राजनीतिक दल अपना संविधान जमा करें

सोमवार को राजनीतिक दलों को भेजी चिट्ठी में चुनाव आयोग ने कहा है कि जब जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29ए के तहत एक राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन होता है, तब उनकी ओर से रूल्स और रेगुलेशन को लेकर मेमोरेंडम भी जमा किया जाता है।

- **पार्टी का संविधान एक आवश्यक दस्तावेज**- आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखा है, ..पार्टी का संविधान एक आवश्यक दस्तावेज होता है, जिसमें पार्टी का उद्देश्य और उसमें लोकतांत्रिक तरीके से काम करने के लिए जरूरी प्रक्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी शामिल होती है। इसलिए यह जानकारी पार्टी के सभी सदस्यों तक भी पहुंचना जरूरी है, जिससे वे इसका पालन कर सकें और आम जनता भी इससे अवगत रहे।
- **पार्टी का संविधान राजनीतिक दलों का दर्पण**– चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टियों से कहा है कि पिछली बार जब उन्होंने दस्तावेज सौंपा था, उसके बाद से उसमें जितने भी बदलाव हुए हैं, उन सबकी कॉपी भी साथ ही जमा करें। इन अपडेटेड कॉपी से पार्टी के अंदर वैधानिक जरूरतों के पालन होते रहने की पुष्टि होती है।

खजुराहो में मोहन कैबिनेट ने लिए दमदार फैसले

सागर से दमोह तक फोरलेन नौरादेही चीतों का नया घर

भोपाल/खजुराहो (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार संपन्न बनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के निर्माण सहित नौरादेही अभ्यारण्य में चीता के रहवास के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने बुंदेलखंड के विकास पर केंद्रित विकास के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने पर करतल ध्वनि से स्वागत किया गया। बैठक में छतरपुर और दमोह के मेडिकल कालेजों में पदों की स्वीकृति सहित शासकीय चिकित्सालयों के उन्नयन और नवीन पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रि-परिषद ने बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सागर के औद्योगिक क्षेत्र 'मसवासी ग्रंट' के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज की मदद से एक निवेशक- हितैषी वातावरण तैयार होगा, जिससे यहां 24 हजार 240 करोड़ रूपये के निवेश के रास्ते खुलेंगे। यह प्रयास सीधे तौर पर 29 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर आर्थिक उन्नयन का नया मार्ग खोलेगा। स्वीकृति अनुसार भूमि प्रब्याजी और वार्षिक भू-भाटक की दर केवल एक रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, विकास शुल्क चुकाने के लिए 20 समान वार्षिक किश्तों की सुविधा दी गई है और संधारण शुल्क 8 रुपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक तय किया गया है।

निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट दी गई है।

सागर से दमोह 76 किलोमीटर फोरलेन मार्ग निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा सागर-दमोह मार्ग, लंबाई 76.680 किमी फोरलेन मय पेव्हड शोल्डर के साथ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत उन्नयन एवं निर्माण के लिए परियोजना वित्तीय लागत 2,059 करोड़ 85 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार लागत का 40 प्रतिशत हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से जीएसटी सहित वहन किया जाएगा। शेष 60 प्रतिशत राशि का प्रावधान संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माही एन्युटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भू अर्जन एवं अन्य कार्यों के लिए 323 करोड़ 41 लाख रूपये का भुगतान भी राज्य बजट से किया जाएगा।

अमरोहा में सोते समय माता-पिता के बीच दबा 26 दिन का मासूम, सुबह मिला बेजान शरीर

अमरोहा (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पति और पत्नी अपने 26 दिन के बेटे के साथ सो रहे थे। मासूम बेटे को बीच में सुलाकर दोनों उसके अगल–बगल खुद लेट गए।

रात में सोते समय गहरी नींद में दोनों ने करवट बदली। इससे बच्चा अपने माता पिता के नीचे दब गया और उसका दम घुट गया। कुछ देर बाद महिला अपने बेटे को दूध पिलाने को उठी तो देखा बच्चे में कोई हरकत नहीं हो रही। महिला ने बच्चे को हिलाया–डुलाया, लेकिन कुछ हरकत नहीं दिखी तो उसके बाद उसने पति को जगाया। पति–पत्नी आनन फानन में 26 दिन के बच्चे को लेकर सीएचसी गजरौला पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बच्चे का प्राथमिक चेकअप करने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनते ही पति–पत्नी फूट–फूटकर रोने लगे। अस्पताल में ही दोनों एक–दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए झगड़ा करने लगे। परिवार के लोगों ने किसी तरह दोनों को समझा–बुझाकर शांत कराया। माता–पिता रोते बिलखते हुए अपने 26 दिन बच्चे के शव को अपने साथ घर ले गए।

देश की पहली स्लीपर वंदे भारत बिहार से

● पटना से दिल्ली 8 घंटे में, लग्जरी होटल जैसी फीलिंग, 160 किमी की स्पीड से दौड़ेगी

पटना (एजेंसी)। राजधानी सा आराम और वंदे भारत जैसी टेक्नोलॉजी, सबसे तेज रफ्तार, इसी महीने से पटना-नई दिल्ली के बीच वह ट्रेन चलने जा रही है, जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।

यह है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन।

ट्रेन 160 किमी घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हो तब भी कप में रखी चाय नहीं गिरेगी। यात्रियों को लग्जरी होटल सा आराम मिलेगा। नहाने के लिए गर्म पानी और टच फ्री टॉयलेट जैसी कई खास सुविधाएं होंगी।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में होंगे 16 कोच– वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 कोच होंगे। इनमें एसी3 के 11, एसी2 के 4 और एसी1 का 1 कोच होगा। कुल 827 सीट होंगे, जिनमें से एसी3 की 611, एसी2 की 188 और एसी1 की 24 सीट होंगी। मांग बढ़ने पर बोगियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। किराया राजधानी एक्सप्रेस के आसपास रखे जाने की उम्मीद है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 27 °c | न्यूनतम 23°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ बुधवार, 10 दिसंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

गोवा क्लब अग्निकांड

थाईलैंड भागे दोनों मालिक: इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी

पणजी (एजेंसी)। गोवा के अरपोरा गांव में 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में 6 दिसंबर की देर रात लगी आग के कुछ घंटे बाद ही क्लब के दोनों मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए। पुलिस ने हादसे के बाद एफआईआर दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू की थी। 7 दिसंबर को दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया, लेकिन इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पता चला कि वे इंडिगो फ्लाइट 6ई 1073 से देश छोड़ चुके थे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने वागाटोर में सौरभ और गौरव लूथरा की रोमियो लेन बीच शैक को गिरा दिया गया।

जयपुर में हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी, ढाई घंटे दहशत

- बम स्क्वॉड ने खाली कराई बिल्डिंग, अफरा-तफरी मची, लगातार दूसरे दिन दहशत

जयपुर (एजेंसी)। जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मंगलवार सुबह करीब 9.43 बजे रजिस्ट्रार सीपीसी को मेल आया था। धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत बिल्डिंग खाली करा ली। मौके पर बम स्क्वॉड को बुलाकर जांच शुरू की गई। इस दौरान बाहर भीड़ जमा हो गई। मौके पर कई सीनियर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। पिछले 40 दिनों में हाईकोर्ट को यह चौथी धमकी मिली है। आज भी सभी सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है।

जज-वकीलों में नाराजगी, कौन भेज रहा मेल?

करीब ढाई घंटे तक चले सर्च के बाद जांच एजेंसियों ने दोपहर 12.30 बजे बिल्डिंग के सुरक्षित होने की जानकारी दी। इसके वकीलों व अन्य लोगों को अंदर जाने दिया गया। बम की धमकियों के कारण लगातार कोर्ट का काम प्रभावित हो रहा है।

भारत ने 101 रन से पहला टी-20 जीता, 74 रन ही बना सका अफ्रीका

- हार्दिक की शानदार फिफ्टी; बुमराह के 100 विकेट पूरे

कटक (एजेंसी)। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले टी-20 में 101 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। मंगलवार को कटक के बाराबाती स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग चुनी। भारत ने हार्दिक पंड्या की फिफ्टी के दम पर 6 विकेट खोकर 175 रन बना लिए। जवाब में मेहमान टीम 74 रन बनाकर ही सिमट गई।

एनरिक नॉर्त्या (एक रन) को अक्षर पटेल ने बोल्ड कर दिया। उन्होंने पावरप्ले के आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने ऐडन मार्करम (14 रन) को बोल्ड कर दिया।

जसप्रीत बुमराह ने केशव महाराज (जीरो) और डेवॉल्ड ब्रेविस (22 रन) को एक ही ओवर में आउट किया। उन्होंने टी-20 इंटरनेशनल में 100 विकेट भी पूरे कर लिए। वरुण चक्रवर्ती ने मार्को यानसन (12 रन) और डोनोवन फरेरा (5 रन) के विकेट लिए। डेविड मिलर (एक रन) को हार्दिक पंड्या ने अपनी पहली बॉल पर आउट किया। अर्शदीप सिंह ने क्विंटन डी कॉक (जीरो) और ट्रिस्टन स्टब्स (14 रन) को पवेलियन भेजा। मैच का स्कोरबोर्ड

पंड्या की फिफ्टी, 100 छक्के भी पूरे-टीम इंडिया की ओर से हार्दिक पंड्या ने सबसे ज्यादा 59 रन (28 बॉल) बनाए। उन्होंने 25 बॉल पर फिफ्टी पूरी की। इतना ही नहीं, पंड्या ने टी-20 इंटरनेशनल में 100 छक्के भी पूरे कर लिए हैं।

डीजीसीए का इंडिगो पर कड़ा एक्शन, एयरलाइन की उड़ानों में पांच प्रतिशत की कटौती

नई दिल्ली (एजेंसी)। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों में 5 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो हर दिन करीब 2,200 उड़ानें चलाती है। अब इसमें से लगभग 110 उड़ानें रोज कम होंगी। एयरलाइन से 10 दिसंबर तक संशोधित शिड्यूल सौंपने को कहा गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, एयरलाइन को इस बारे में बता दिया गया है और कौन-कौन सी उड़ानें कम की जाएंगी, इसकी सूची तैयार की जा रही है।

मंजूर उड़ानों के मुकाबले कम संचालन- डीजीसीए की ओर इंडिगो को जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि विंटर शेड्यूल के तहत नवंबर 2025 के लिए एयरलाइन को प्रति सप्ताह 15,014 प्रस्थान और कुल 64,346 उड़ानों की मंजूरी दी गई थी। हालांकि, परिचालन आंकड़ों से पता चलता है कि इंडिगो केवल 59,438 उड़ानें ही संचालित कर पाई।

वन्यजीव संरक्षण के लिए अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड

- यह प्रतिष्ठित अमेरिकी अवॉर्ड पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई बने

नई दिल्ली/ वाशिंगटन (एजेंसी)। वन्यजीव संरक्षण और पशु कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए अनंत अंबानी को अमेरिका में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में 'ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें वनतारा के जरिए जानवरों के बचाव, इलाज, पुनर्वास और संरक्षण में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया। इस उपलब्धि के साथ अनंत अंबानी ने एक खास रिकॉर्ड भी बनाया है। वह इस सम्मान को पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले यह अवॉर्ड अमेरिकी राष्ट्रपतियों जॉन एफ कैनेडी और बिल क्लिंटन सहित हॉलीवुड हस्तियों और कई वैश्विक नेताओं को दिया जा चुका है।

नवजोत कौर फिर बोलीं- चोरों का साथ नहीं दूंगी

अमृतसर (एजेंसी)। पंजाब कांग्रेस से सस्पेंड किए जाने के बावजूद नवजोत कौर सिद्धू के तेवर तीखे हैं। मंगलवार को अमृतसर में नवजोत कौर ने सस्पेंड किए जाने पर राजा वड़िंग के लिए कहा- यह कार्रवाई उस प्रधान ने की, जिसे कोई नहीं मानता। राणा गुरजीत भी इसी नोटिस से चल रहे हैं। मेरी हाईकमान से बात हो रही है। हम चोरों का साथ नहीं देंगे। अगर 4-5 लोगों को हटा दें तो फिर देखेंगे।

लखनऊ में गुरिल्ला बनकर रह रहे बांग्लादेशी-रोहिंग्या

- नाम पूछने से पहले आईडी कार्ड दिखाते हैं, 7335 झुग्गी-झोपड़ियों में 90 प्रतिशत मुस्लिम

लखनऊ (एजेंसी)। लखनऊ में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का हर काम में एक पैटर्न है। ये सभी खुद को असम के बारपेटा का निवासी बताते हैं। ये घुसपैठिए झुग्गी-झोपड़ी में गुरिल्लों की तरह रहते हैं। सभी के पास पास एनआरसी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड हैं। नाम पूछने से पहले सभी अपना आइडी कार्ड दिखाते हैं। जिन झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वहां के स्थानीय नेताओं और प्रभावशाली लोगों का इनको संरक्षण है। क्योंकि ये वोटर भी बन चुके हैं। तकरीबन 90 प्रतिशत असमी-बांग्लादेशी हैं।

सीएम योगी की सख्ती, पुलिस और एटीएस ने मांगी रिपोर्ट- लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान उजागर करने और इन्हें डिपोर्ट करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय की तरफ से एक्शन के बाद पूरा महकमा सक्रिय हो गया है।

- अखिलेश बोले-

एसआईआर के बहाने एनआरसी का काम

नई दिल्ली (एजेंसी)। शीतकालीन सत्र के 7वें दिन मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) पर चर्चा चल रही है। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यूपी के सीएम कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। जो ये खुलकर नहीं कर सकते हैं वो एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बनकर रह गया है। चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि पांच लाख वोटर डिलीट, छह लाख वोटर डिलीट और बीजेपी जश्न मना रही है। मनीष तिवारी बोले- चुनाव आयोग एसआईआर नहीं करा सकता, ये गैरकानूनी इससे पहले चर्चा की शुरूआत कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि देश के 12 राज्यों में किया जा रहा एसआईआर गैरकानूनी है। संविधान में पूरे राज्य में एक साथ एसआईआर को लेकर कोई कानून नहीं है, इसे तत्काल रोकें।

सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट का नोटिस

1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाने का आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस दिया है। यह नोटिस उस याचिका पर आया है, जिसमें दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया था। इसके अलावा याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है और पूरे केस का रिकॉर्ड (टीसीआर) मंगाया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। इस दौरान सोनिया और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देना होगा।

सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी, हिमाचल के रोहतांग में मनाली-लेह रोड बंद

नई दिल्ली/देहरादून/भोपाल/लखनऊ (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। कई शहरों में रात को तापमान 6 डिग्री से नीचे चला गया। मप्र शहडोल के कल्याणपुर में सबसे कम तापमान 4.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। भोपाल, इंदौर समेत 9 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे जा सकता है।

राजस्थान के 19 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। फतेहपुर में सबसे कम, 4.4 डिग्री पारा दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने राज्य में 10 दिसंबर से शीतलहर चलने की आशंका जताई है।

दूसरी तरफ, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में दोपहर को तेज बर्फबारी हुई। पहाड़ पूरी तरह से सफेद नजर आए।

नीतीश कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया, दो नए जिले भी बने

- बिहार सरकार ने विकास कार्यों को दी गति

पटना (एजेंसी)। नीतीश सरकार की कैबिनेट की दूसरी बैठक मंगलवार को हुई। इसमें 19 एजेंडे पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। यह एक जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मो इम्तियाज के पुत्र मो इमदाद रजा को अनुकंपा पर नियुक्ति दी जाएगी।

कैबिनेट ने तीन नए विभागों के गठन को भी मंजूरी प्रदान की है। युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं नागर विमाननन विभाग की स्थापना होगी। इसके साथ ही लघु-मध्यम उद्यम निदेशालय एवं विपणन प्रोत्साहन निगम बनाए जाएंगे।

षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन व पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी कर्मियों, पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2025 के प्रभाव से 252 की जगह 257 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

बाल साहित्य को सभी विधाओं में समृद्ध बनाने की जरूरत है- हिंदी लेखिका संघ की कार्यशाला में विशेषज्ञों का मत

भोपाल। हिंदी लेखिका संघ की बाल साहित्य कार्यशाला में देशभर से आए साहित्यकारों ने कहा कि आज बाल साहित्य को कहानी, कविता और नाटक से आगे बढ़ाकर सभी विधाओं में विकसित करने की आवश्यकता है। वक्ताओं ने बच्चों की कल्पनाशीलता, संवेदना, भाषा कौशल और बौद्धिक विकास को केन्द्र में रखकर नए और प्रासंगिक लेखन की आवश्यकता पर जोर दिया।

दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में मंगलवार को आयोजित हिंदी लेखिका संघ की बाल साहित्य कार्यशाला में साहित्य अकादमी (मध्यप्रदेश) के निदेशक और वरिष्ठ बाल साहित्यकार डॉ. विकास दवे ने कहा कि हिंदी बाल साहित्य की परंपरा अत्यंत समृद्ध है, परंतु यह मुख्यतः कविता, कहानी और नाटक तक सीमित है। बाल मनोविज्ञान, विज्ञान-लेखन, यात्रा-वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी, हास्य-विनोद और अन्य विधाओं में भी रचनात्मक कार्य की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि बाल साहित्यकार को अपनी कल्पनाओं की खिड़की पूरी तरह खोलनी चाहिए,

और लेखन केवल सामान्य बच्चों तक सीमित न होकर मूक-बधिर व दिव्यांग बच्चों के लिए भी होना चाहिए। 'बाल साहित्य को आनंददायक बनाना सबसे महत्वपूर्ण है,' उन्होंने कहा। संस्था अध्यक्ष डॉ. साधना गंगराड़े ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि बाल साहित्य एक बीज की तरह है, जिसे यदि बाल-मन की गीली मिट्टी में बोया जाए तो भविष्य एक सुंदर बगिया बनकर विकसित होता है। उन्होंने कहा कि बाल साहित्य बच्चे के व्यक्तित्व, भाषा, विचार और मनोवैज्ञानिक विकास की पहली पाठशाला है। इसलिए लेखिकाओं का दायित्व है कि वे बाल मन को सही दिशा देने वाला संवेदनशील, मूल्यनिष्ठ और आनंददायक साहित्य रचें। प्रथम सत्र में जबलपुर की बाल साहित्यकार डॉ. मंजरी शुक्ला ने कहा कि कहानियाँ बच्चे को कल्पना लोक की यात्रा कराती हैं, जहाँ परियाँ, जादूगर, बोलने वाले पशु-पक्षी और उड़ने वाले ड्रैगन उसकी संवेदनाओं को विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि बाल साहित्यकार को बच्चों के मानसिक स्तर तक उतरकर लिखना जरूरी है, क्योंकि बच्चा प्रेम और संवाद को बिना किसी पूर्वाग्रह के अपनाता है।

केंद्रीय मंत्री बोले- आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही, इससे आर्थिक निर्भरता जैसी चुनौतियां बढ़ेगी

2036 तक हर 7 में 1 भारतीय सीनियर सिटिजन होगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। 2011 में देश में 60 साल से ऊपर की आबादी 10.16 करोड़ थी, जो 2036 तक बढ़कर 22.74 करोड़ हो जाएगी। यानी बुजुर्गों की आबादी का हिस्सा कुल जनसंख्या में 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो जाएगा और हर 7 में 1 भारतीय सीनियर सिटिजन होगा। ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, उनके सामने स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक निर्भरता और डिजिटल सुविधाओं का उपयोग जैसी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं।

सरकार ने माना है कि जैसे-जैसे देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, परिवारों का ढांचा और रिश्तों का तरीका भी बदल रहा है। पहले ज्यादातर लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, जहां बुजुर्गों की देखभाल सब मिलकर करते थे। अब छोटे परिवार बढ़ रहे हैं, जिससे बुजुर्गों की देखभाल का तरीका भी बदल गया है और उनकी जिम्मेदारी कम लोगों पर आ गई है। नई रिपोर्टों में इसे विरोधाभास कहा गया है, यानि बुजुर्गों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन समाज की सोच, जिम्मेदारी और उनकी देखभाल को लेकर उम्मीदें पहले जैसी नहीं रहीं। इसका सीधा असर बुजुर्गों की देखभाल और उनके सम्मान पर पड़ रहा है।

गृह राज्य मंत्री बोले- सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन्स बनाई-गृह राज्य मंत्री ने बताया कि बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से अटल वयो अभ्युदय योजना लागू की है। इस योजना के तहत पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता और सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन्स भी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय-अधिकारिता मंत्री करते हैं। इस परिषद में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हैं, जो बुजुर्गों से जुड़े मुद्दों पर सलाह देते हैं।

2023: नीति आयोग ने कहा - 2050 तक पांचवा भारतीय बुजुर्ग होगा

इससे पहले 2023 में नीति आयोग ने बताया था कि दुनियाभर में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी बढ़ रही है। भारत में भी जन्मदर गिरने से बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। 2050 तक कुल जनसंख्या के 19.5 प्रतिशत बुजुर्ग होंगे, जो फिलहाल 10 प्रतिशत हैं। अभी कुल आबादी में 10.40 करोड़ लोग बुजुर्ग हैं। अनुमान है कि 2050 तक हर पांचवा भारतीय बुजुर्ग होगा। 'भारत में वरिष्ठ नागरिक देखभाल सुधार वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में नीति आयोगन ने बुजुर्गों के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने, अनिवार्य बचत के लिए रिवर्स मॉर्टगेज सिस्टम शुरू करके बुजुर्ग देखभाल सेवाओं को विकसित करने का आह्वान किया था।

नीति आयोग के सुझाव

बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रौद्योगिकी और एआई के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जाए। स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को डिजाइन करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए। बुजुर्गों को वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत। वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल उपकरणों तक पहुंच में सुधार हो।

बुजुर्गों की देखभाल का 60 हजार करोड़ का कारोबार- आयोग के अनुसार, भारत में वरिष्ठ नागरिक देखभाल उद्योग करीब 60 हजार करोड़ रु. है। इसके तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। आयोग ने कहा कि घरों पर ही बुजुर्ग की देखभाल और मोबाइल अस्पताल बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने स्टे हटाया, अब एवरेस्ट विजेता भावना को 'विक्रम अवॉर्ड' मिलना आसान

'एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी' में विक्रम अवॉर्ड पाने वाली वे पहली महिला होंगी

इंदौर। माउंट एवरेस्ट फतह कर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली पर्वतारोही भावना डेहरिया को अब विक्रम अवॉर्ड मिलने का रास्ता साफ हो गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को उनके चयन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराया। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने आदेश सुनाते हुए कहा कि 2023 के 'एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी' के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय नियमों के अनुरूप है और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

यह महत्वपूर्ण जानकारी एडवोकेट अनुनय श्रीवास्तव, जो मामले में भावना डेहरिया की ओर से उपस्थित थे, द्वारा साझा की गई। वहीं, राज्य सरकार की ओर से इस मामले में डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रेय राज सक्सेना ने प्रभावी तरीके से पक्ष रखा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया। यह याचिका मधुसूदन पाटीदार द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वे भावना डेहरिया से वरिष्ठ हैं और उन्हें ही पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि पाटीदार का एवरेस्ट आरोहण वर्ष 2017 का है, जो मध्य प्रदेश पुरस्कार नियम, 2021 के अनुसार निर्धारित पांच वर्ष की पात्रता अवधि से बाहर है। नियम 5 के अनुसार एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी में केवल पिछले पांच वर्षों के उपलब्धियों को ही मान्य किया जा सकता है। इस आधार पर अदालत ने कहा कि पाटीदार वर्ष 2023 के पुरस्कार के लिए पात्र ही नहीं थे, इसलिए उनका दावा सही रूप से अस्वीकार किया गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया वर्ष 2021, 2022 और 2023 में नियमों के अनुरूप रही है, इसलिए अपर्याप्त जानकारी या नोटिस न देने का आरोप भी टिकाऊ नहीं है।

याचिका 'निर्मूल' पाए जाने के बाद अब भावना डेहरिया को विक्रम अवॉर्ड प्रदान करने में कोई बाधा नहीं रही। राज्य सरकार जल्द ही उन्हें आधिकारिक समारोह में सम्मानित करेगी। छिंदवाड़ा जिले के तामिया गांव की निवासी भावना डेहरिया ने दुनिया की पाँच महाद्वीपीय सबसे ऊँची चोटियों पर भारत का तिरंगा फहराया। इनमें माउंट एवरेस्ट (एशिया), किलिमंजारो (अफ्रीका), कोज़िअस्को (ऑस्ट्रेलिया), एलब्रुस (यूरोप) और अकोंकागुआ (दक्षिण अमेरिका) शामिल है। भावना डेहरिया मध्य प्रदेश से एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिलाओं में शामिल हैं और अब एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी में विक्रम अवॉर्ड पाने वाली पहली महिला भी बनेंगी। वे और उनकी चार वर्षीय बेटी सिद्धि, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की ब्रांड एंबेसडर भी हैं। भारतीय हिमालय को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने एक अनूठा गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया है। भावना ने कहा कि यह पुरस्कार उनके साहस, लगन और पर्वतारोहण में समर्पण का सम्मान है।

19.85 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार

इंदौर। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर शहर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत क्राइम ब्रांच को एक और बड़ी सफलता मिली। लाभ श्री कॉम्प्लेक्स के सामने पत्थर गोदाम रोड क्षेत्र से एक संदिग्ध युवक को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 19.85 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब दो लाख रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तस्करों की तलाश के दौरान गश्त कर रही थी, तभी रेलवे स्टेशन की ओर से आ रहा एक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया। संदेह होने पर उसे रोका गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मनीष उर्फ मोंटू जायसवाल निवासी बाणगंगा इंदौर बताया। तलाशी ली तो उससे ब्राउन शुगर के पैकेट बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 में प्रकरण दर्ज किया है। मामले की विवेचना जारी है तथा सप्लाई चैन की कड़ियों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शहर में नशे के खिलाफ अभियान और अधिक सख्ती से जारी रहेगा।

बीएसएनएल के बकाया बिलों पर 50% तक छूट

इंदौर। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश पर आगामी 13 दिसंबर (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल इस लोक अदालत में बकाया लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच और मोबाइल पोस्टपेड बिलों से जुड़े प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निपटान करेगा। बीएसएनएल ने बताया कि लोक अदालत में बकाया राशि जमा करने पर उपभोक्ताओं को नियमानुसार 10 से 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं के अनुरोध पर लीज्ड सर्किट,लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड,एफटीटीएच और मोबाइल सेवाओं को पुनः प्रारंभ करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उपभोक्ता अपने बिल संबंधी मामलों का निपटारा जिला न्यायालय इंदौर,तहसील महू के अलावा बीएसएनएल नेहरू पार्क स्थित कार्यालय के राजस्व अनुभाग में भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कर सकते हैं। यह छूट उपभोक्ताओं के लिए बकाया निपटाने का महत्वपूर्ण अवसर है।

अनिका के इलाज के लिए मानवीय संवेदना

इंदौर। बेबी अनिका शर्मा के उपचार हेतु 9 करोड़ रुपए को आवश्यकता है। अनिका के माता पिता लगत जनसहयोग से उसके उपचार की राशि एकत्रित कर रहे है। इसी कड़ी में विधायक गोलू

शुक्ला के बेटे अंजनेश ने भी अपनी शादी के अवसर पर पांच लाख की राशि अनिका के उपचार के लिए भेंट कर अनूठा उदाहरण दिया है। जहां कलेक्टर शिवम वर्मा के बाद विधायक शुक्ला ने भी अनिका के उपचार के लिए लोगों से अपील की है। विधायक शुक्ला ने अपने परिवार से इसकी शुरुआत करते हुए आमजन से अपील की है कि अनिका की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और यथासंभव जन सहयोग प्रदान कर उसके जीवन को बचाने में अपनी भागीदारी निभाएँ। अनिका जैसे मासूम के जीवन में आशा की किरण तभी प्रज्वलित होगी जब समाज एकजुट होकर सहयोग का हाथ बढ़ाएगा। गौरतलब है कि कलेक्टर शिवम वर्मा ने अनिका के उपचार के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों से चर्चा कर रहे है और लोगों से सहयोग की अपील भी कर रहे है।

गुजरात, राजस्थान से 61 गुमशुदा बच्चे ढूंढे

इंदौर। जोन-2 पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। एक नवंबर 2025 से चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का लक्ष्य क्षेत्र के गुमशुदा बच्चों को खोजकर सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचाना है। पुलिस की सतत मेहनत, तकनीकी विश्लेषण और विभिन्न राज्यों में की गई खोजबीन के परिणामस्वरूप कुल 61 बच्चे, जिसमें 13 बालक एवं 48 बालिकाएं शामिल है, को सुरक्षित बरामद कर उनके परिवारों के सुपुर्द किए गए। इसके अंतर्गत थाना कनाड़िया के एक मामले में गुम हुई बालिका को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जामनगर (गुजरात) से सकुशल बरामद किया गया। थाना लसूड़िया के अलग-अलग प्रकरणों में वर्ष 2025 में लापता बालिकाओं को दिल्ली, गुजरात एवं मुंबई से खोजकर परिजनों तक पहुंचाया गया। वर्ष 2017 में थाना खजराना क्षेत्र से गुम हुई नाबालिग बालिका को 8 वर्ष बाद तकनीकी सहायता से ढूंढकर परिवार से मिलाया गया। अन्य मामलों में भी वृंदावन (उत्तर प्रदेश), जयपुर, ललितपुर, जामनगर और दिल्ली से भी बच्चों को ढूंढ निकाला।

भाजयुमो नगर अध्यक्ष की बारात में हर्ष फायरिंग

इंदौर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा की बारात में जमकर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। 5 दिसंबर को तेजाजी नगर क्षेत्र से गोल्डन ब्लॉसम रिसॉर्ट तक निकली इस बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में शराब माफिया और बीजेपी से जुड़े स्थानीय नेता को बंदूक और पिस्तौल से फायर करते हुए देखा जा सकता है। बारात में मेयर पुष्यमित्र भार्गव, राऊ विधायक के प्रतिनिधि और स्थानीय पार्षद भी मौजूद थे। मेयर का बारात में नाचते हुए वीडियो भी सामने आया है। हालांकि, नेताओं ने हर्ष फायरिंग की जानकारी होने से इनकार किया है। इससे पहले भी करीब एक महीने पहले करणी सेना और बीजेपी से जुड़े पृथ्वी सिंह द्वारा बारात में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसमें खजराना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। जांच में पता चला था कि फायरिंग पृथ्वी सिंह ने लाइसेंसी बंदूक से की थी। पुलिस का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मामले में कार्रवाई जारी है। उधर, क्राइम ब्रांच के एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ़ इंडिया का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से इंदौर में

इंदौर। न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ़ इंडिया (एनएसआई) अपना 73वां वार्षिक सम्मेलन एनएस आईकॉन 2025 इंदौर में आयोजित करेगी। यह कार्यक्रम 10 से 14 दिसंबर तक ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस वर्ष एनएसआई अपनी स्थापना के 75 साल पूरे कर रही है। इसलिए यह सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंदौर में यह सम्मेलन तीसरी बार हो रहा है। इससे पहले 1999 और 2004 में इसका सफल आयोजन हुआ था। अच्छे अनुभवों के कारण 75वीं वर्षगांठ का आयोजन इंदौर को दिया गया। सम्मेलन का उद्घाटन 11 दिसंबर को दोपहर 12 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विशेष अतिथि रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन डॉ वसंत डाकवाले और सेक्रेटरी डॉ जेएस कठपाल ने बताया कि इस बार 700 से अधिक वैज्ञानिक प्रस्तुतियां होंगी। इनमें शोधपत्र, केस स्टडी, वीडियो और डिबेट शामिल हैं। 10 दिसंबर को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिलिकॉन 2025 का आयोजन होगा। इसमें नर्सों को न्यूरो-केयर की ट्रेनिंग दी जाएगी। सम्मेलन में अमेरिका, यूरोप और ब्राजील से प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन भाग लेंगे, जिसमें डॉ डेनियल जे होह, डॉ टॉर्स्टिन आर मेलिंग, डॉ पाउलो हेनरिक और डॉ लुईस बोर्बा प्रमुख नाम हैं। सम्मेलन की शुरूआत 7 विशेष हैंड्स-ऑन कार्यशालाओं से होगी।

पतंग उड़ाने वालों पर पुलिस ड्रोन से नजर रखेगी, चाइनीज पर कार्रवाई

छापामार कार्रवाई कर अब तक 1500 मांझा रोल बरामद किए

इंदौर। शहर में चाइनीज मांझा से होने वाले हादसे रोकने अब पुलिस सख्ती का डंडा चलाने जा रही है। ड्रोन से पतंगबाजों पर नजर रखी जाएगी। पतंगबाजों तक पहुंचकर पुलिस मांझा चेक करेगी। मांझा देशी मिला तो ठीक, चाइनीज मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा उपयोग करने वाले ड्रोन से पांच किलोमीटर की परिधि में देखा जा सकेगा। कलेक्टर ने इस जानलेवा मांझा के उपयोग करना प्रतिबंधित है। पुलिस लगातार मांझा जब्ती में लगी है। दुकानों पर छापामार कार्रवाई कर वहां से अब तक 1500 मांझा रोल बरामद कर चुकी है। मामले में कुछ दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई थी। एक सप्ताह पहले तीन नाबालिग दोस्त रालामंडल से घूम कर लौट रहे थे। तभी चाइनीज मांझा की चपेट में आने से एक नाबालिग की मौत हो गई थी। वहीं दोनों दोस्त जख्मी हो गए थे। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया था। लोगों को चाइनीज मांझा के उपयोग नहीं करने तथा इसके दुष्परिणामों से अवगत कराने लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रैलियां निकाली जा रही है, इसके बावजूद हादसों में कमी नहीं आ रही है।

इसलिए उठा रही कदम

हादसे के बाद पुलिस केवल जब्ती अभियान चलाती है। अब पुलिस ड्रोन की मदद से हर पतंगबाज पर नजर रखेगी। पतंगबाजों के फोटो ड्रोन में कैद हो जाएंगे। इसका रिकॉर्ड लंबे समय से सुरक्षित रखा जाएगा। जिस क्षेत्र या रोड पर चाइनीज मांझा से हादसा होगा, वहां के पतंगबाजों को थाने बुलाकर पूछताछ की जाए। ड्रोन से उनकी पहचान आसानी से हो सकेगी।

खींचने, लहराने के दौरान हादसा

आमतौर पर पंतग कटने के बाद मांझा सड़क और बिजली के तार से होकर निकलता है। कई पतंगें भी अधिक मांझा से कटने के कारण लहराती हुई निकलती है। लहराने वाले मांझा राहगीर को नुकसान पहुंचाता है। यह भी देखा गया है कि पतंग कटने के बाद पतंगबाजी दूर से मांझा खींचता है, इससे भी हादसा होता है। ड्रोन कैमरे से खींचने, लहराने की जानकारी भी मिल सकेगी। पिछले दिनों खजराना पुलिस ने बाबा फरीद नगर में छापा मारकर दुकान से 912 मांझा की रील जब्त की थी। दुकान पर कई काटूर्नों में मांझा आया था। पुलिस को दुकानदार ने ट्रांसपोर्ट और लोडिंग वाहन की मदद से कार्टून आना बताया था, अब पुलिस ट्रांसपोर्टर और वाहन चालक पर कार्रवाई करेगी, ताकि यह पता चल सके कि कहां से मांझा इंदौर डिलीवर हो रहा है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जोन 2) अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि चाइनीज मांझा का उपयोग करने वालों पर बिना दबाव प्रभाव कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से पतंगबाजी पर भी नजर रखेंगे। जिस क्षेत्र में हादसे होंगे, वहां के पतंगबाजों पर कार्रवाई करेंगे।

ट्रैफिक पुलिस का अभियान, नो पार्किंग हेलमेट, ऑटो और ई-रिक्शा पर सख्ती

671 बिना हेलमेट, 119 गलत पार्किंग, 35 ऑटो, ई-रिक्शा पर कार्रवाई

इंदौर। सड़क सुरक्षा और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने शहरभर में विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत सबसे पहले बिना हेलमेट दोपहिया चालकों पर सख्त कार्रवाई की गई। इस अभियान में कुल 671 वाहन चालकों पर चालान काटा गया। पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि अपने और परिवार की सुरक्षा हेतु हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।

इस क्रम में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की गई। शहर के प्रमुख बाजारों,चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अभियान चलाकर 119 वाहनों को गलत पार्किंग के लिए चालान कर हटाया गया। पुलिस ने बताया कि ऐसे वाहन आम जनता के आवागमन में बाधा बनते हैं और कई बार जाम जैसी स्थिति पैदा करते हैं। दुकानदारों और संस्थानों को निर्धारित पार्किंग का उपयोग करने की समझाइश भी दी गई। इसके अलावा ऑटो एवं ई-रिक्शा चालकों पर भी विशेष मुहिम के तहत कार्रवाई हुई।

प्रतिबंधित मार्गों पर संचालन, ओवरलोडिंग और नो पार्किंग जोन में खड़े होने जैसे उल्लंघनों पर 35 ऑटो व ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ चालान किया गया। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थान पर ही खड़े करें, नियमों का पालन करें और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।

कांग्रेस का हल्ला बोल, एसआईआर से 5.68 लाख मतदाता 'गायब' हुए

सूची सार्वजनिक करने की मांग, पारदर्शिता पर गंभीर सवाल

इंदौर। मतदाता सूची के सत्यापन से जुड़ी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हाल ही में संपन्न हुई एसआईआर कार्रवाई में लाखों मतदाताओं के नाम सूची से गायब पाए गए हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर मतदाता सूची में राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा कि यह मताधिकार से खिलवाड़ है। कांग्रेस का दावा है कि इंदौर जिले में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कुल 5 लाख 68 हजार मतदाता लापता मिले हैं। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में शहर की 9 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कुल 4,17,717 वोटों का अंतर था। इस तुलना को रखते हुए कांग्रेस ने तर्क दिया कि गायब मतदाताओं की संख्या चुनावी अंतर से कहीं अधिक है, जो अपने आप में संदेह पैदा करती है और जांच की मांग को मजबूत करती है।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की कि जिन मतदाताओं की एसआईआर प्रक्रिया अधूरी रही है या जो अपने पते पर अनुपलब्ध मिले हैं, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए। पार्टी ने कहा कि बिना उचित सत्यापन के इन नामों को दोबारा मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी। पार्टी ने इसे लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की विश्वसनीयता से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया।

आबकारी अधिकारी के निलंबन के बाद अब नई नियुक्ति की गई

प्रभारी मनीष खरे को तत्काल अतिरिक्त जिम्मेदारी दी

देवास। देवास के शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना की आत्महत्या मामले ने प्रदेश के आबकारी विभाग में हलचल मचा दी। घटना के बाद निलंबित की गई सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित के स्थान पर अब शासन ने नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की है। इस बीच वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश ने संकेत दे दिया कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। शासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त, मुख्यालय ग्वालियर मनीष खरे को देवास जिले के सहायक आबकारी आयुक्त के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से सौंपा जाता है। यह जिम्मेदारी उन्हें उनके वर्तमान दायित्वों के साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक निभानी होगी। मकवाना की आत्महत्या के बाद वायरल हुए वीडियो में लगाए गए उगाही के गंभीर आरोपों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे।

वीडियो के आधार पर शासन ने पहले मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित किया, अब देवास में प्रशासनिक मोर्चे को संभालने के लिए अनुभवी अधिकारी को जिम्मेदारी देकर संकेत दिया है कि आगे और कदम उठाए जा सकते हैं। इधर,देवास जिले में नए प्रभारी की नियुक्ति को लेकर स्थानीय स्तर पर भी हलचल है। शराब ठेकों से जुड़े व्यापारी वर्ग और परिजन लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मनीष खरे की नियुक्ति के साथ अब जांच और प्रशासनिक कार्रवाई की रफ्तार और बढ़ेगी। प्रदेश भर में यह मामला अब विभागीय शुचिता और पारदर्शिता की बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है।

दो शासकीय सेवक निलंबित, बेसमेंट पार्किंग व फायर ऑडिट पर एक्शन

कलेक्टर की बड़ी सर्जरी, शिकायतकर्ताओं को सामने बुलाया

इंदौर। जिला प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कलेक्टर शिवम वर्मा ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए समय-सीमा एवं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा बैठक में शिकायतकर्ताओं को सीधे समक्ष में बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान कराया। इस नई व्यवस्था ने बैठक को विशेष रूप से प्रभावी और कार्रवाई-केन्द्रित बना दिया।

बैठक में कलेक्टर वर्मा ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार आम जनता से जुड़े राजस्व, नामांकन, सीमांकन और हेल्पलाइन प्रकरणों में किसी भी स्तर पर विलंब स्वीकार्य नहीं है। लंबित मामलों की समीक्षा में लापरवाही सामने आने पर दो शासकीय सेवकों को तत्काल निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सख्त संदेश दिया गया। शिकायतकर्ता सुभाष मस्करा की पात्रता पर्ची संबंधी शिकायत पर ग्राम पंचायत मोरोद के सचिव को निलंबित किया गया, जबकि समग्र आईडी में लापरवाही पाए जाने पर झोनल कार्यालय के ऑपरेटर को भी निलंबित करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड लोन की गड़बड़ी तथा आयुष्मान कार्ड राशि दुरुपयोग संबंधी मामलों में संबंधित विभागों पर जिम्मेदारी तय कर त्वरित समाधान के निर्देश जारी किए गए।

यातायात सुधार के लिए कलेक्टर ने शहर में 134 चिन्हित बेसमेंट पार्किंग की पुनः जांच का अभियान शुरू करने की घोषणा की। जहां पार्किंग का उपयोग बंद पाया जाएगा, वहां कठोर कार्रवाई होगी और जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जाएगी। अग्नि सुरक्षा को लेकर भी कलेक्टर ने शहर की सभी बड़ी इमारतों में अनिवार्य फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए और मानक अनुपालन न मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी।

चाइनीज मांझा,अवैध बायोडीजल भंडारण और अवैध कारखानों पर भी आगामी दिनों में सख्त कार्रवाई जारी रहने के संकेत देते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कड़ा रुख अपनाने के निर्देश दिए।

अलग-अलग हादसों में दो नाबालिगों की मौत

इंदौर। शहर में रविवार-सोमवार को दो अलग-अलग हादसे हुए। एक हादसे में नाबालिग ने फांसी लगाई तो दूसरे में करंट लगने से मौत हो गई। आजाद नगर पुलिस के अनुसार मृतक सुमित (16) पिता दिनेश मूल रूप से खातेगांव का रहने वाला था और करीब एक साल से इंदौर में बारदान कारखाने में काम कर रहा था। रविवार रात ठेकेदार के कॉल पर उसके साथी घर पहुंचे तो वह फंदे पर लटका मिला। इससे पहले मकान मालिक भी उसे देख चुका था। पुलिस को कमरे से शराब की बोतल और खाने का सामान मिला। आशंका है कि सुमित ने किसी दोस्त के साथ शराब पीने के बाद यह कदम उठाया। शव का पोस्टमार्टम एमवाय अस्पताल में कराया जा रहा है।पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दूसरी घटना में चंदन नगर थाना क्षेत्र के बांक में रहने वाले अब्दुल हफीज (14) पिता अब्दुल रज्जाक खत्री की मौत हो गई। वह रात 12 बजे बकरा-बकरी को खाना देने उतरा था। इसी दौरान उसका हाथ पानी की मोटर के खुले तार से टकरा गया और उसे जोरदार करंट लगा। हफीज चार भाइयों में सबसे छोटा था। पिता पहले नाश्ते की दुकान चलाते थे।

संपादकीय

वंदे मातरम्, निशाना नेहरू!

राष्ट्रगान वंदे मातरम् पर सोमवार को लोकसभा में जो दस घंटे की चर्चा हुई, उसका लुब्बो लुआब सिर्फ इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना वंदे मातरम् गीत को अक्षरशः स्वीकार न करने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को गरियाना था। हर मुद्दे पर नेहरू को जिम्मेदार ठहराने की राजनीतिक चाल से अब जनता भी ऊबने लगी है। फिर भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वंदे मातरम् पर अपने 60 मिनट के भाषण में जहां आजादी के आंदोलन में बांग्ला लेखक बंकिमचंद्र चटर्जी लिखित 'वंदे मातरम्' गीत में निहित राष्ट्रभक्ति का जिक्र किया, वहीं कांग्रेस पर इस गीत के टुकड़े करना आरोप भी लगाया। मोदी ने अपने भाषण में 13 बार कांग्रेस, 7 बार नेहरू और 3 बार जिन्ना का जिक्र किया। गौरतलब है कि लोकसभा में यह विशेष चर्चा वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर आयोजित की गई थी। विषय पर चर्चा की शुरूआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कहा कि वंदे मातरम् अंग्रेजों को करारा जवाब था, ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा। महात्मा गांधी को भी यह गीत पसंद था। उन्हें यह नेशनल एंथम के रूप में दिखता था। उनके लिए इस गीत की ताकत बड़ी थी। फिर भी पिछले दशकों में इसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम् के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी, जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी। अपने एक घंटे के भाषण में मोदी ने वंदे मातरम् का 121 बार, देश 50, भारत 35, अंग्रेज 34, और बंगाल का 17 बार जिक्र किया। साथ ही वंदे मातरम् के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम 10 बार, महात्मा गांधी 6 बार, मुस्लिम लीग 5 बार, संविधान 3 बार, मुसलमान 2 बार और तुष्टिकरण का 3 बार जिक्र किया। मोदी के आरोपों का सार यही है कि कि वंदे मातरम् के मुद्दे पर नेहरू जिन्ना के सामने झुक गए। और अतंतः वंदेमातरम् के दो ही अंतरे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत हुए। मोदी का तर्क था कि इस गीत को पूरा स्वीकार किया जाना था, जोकि संस्कृत और बांगला दोनों भाषाओं में है और काफी लंबा है। यहां सवाल उठता है कि जिस गीत को भारत के अधिकांश लोग स्वीकार कर चुके हैं, जो अब अधिकृत राष्ट्रगान है, विधानमंडलों और आयोजनों में गाया जाता है, उसको लेकर दस घंटे तक चर्चा करना संसद के कीमती समय का सौ फीसदी सदुपयोग नहीं कहा जा सकता। यूं कुछ मुसलमान अभी भी इस गीत को मूर्ति पूजा से जोड़कर इसे गाने से इंकार करते रहे हैं, लेकिन वह विरोध राजनीतिक ज्यादा है और उसका कोई खास महत्व नहीं है। इस बारे में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का यह कटाक्ष गलत नहीं है कि इस चर्चा का असल उद्देश्य तीन माह बाद पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं, क्योंकि इस गीत के रचयिता बंकिमबाबू बंगाली थे और इस बहाने वहां राष्ट्रवाद को नई हवा दी जा सकती है। उनका यह सवाल भी वाजिब था कि जब वंदे मातरम् को देश ने स्वीकार कर ही लिया है तो उस पर चर्चा किस बात की ? इतिहास तो सबको पता है। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप को खारिज किया है। तारीख की हर गलती का ठीकरा नेहरू पर फोड़ने से भाजपा का तात्कालिक सियासी हित भले ही सधता हो, लेकिन उससे बाकी कुछ भी सिद्ध नहीं होता। आज देश में सामने कई गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, जिनमें इंडिगो संकट पहला है और इस पूरे प्रकरण में सरकार जिस तरह एक निजी कंपनी के आगे झुकती दिख रही है, वह एक मजबूत देश और सरकार के लिए अच्छा लक्षण नहीं है।

क्या इंडिगो संकट किसी नए बदलाव की आहट है?

नजरिया

डॉ.सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

जाहिर है कि घरेलू नागरिक उड्डयन लगभग ठप्प था। फलतः खामियाजा उन लाखों मुसाफिरों ने भुगता, जो हवाई यात्रा को निरापद, सुविधाजनक और त्वरित मानकर वरियता देते थे। बदइंतजामी का आलम यह था कि दिल्ली से सोमवार आठ दिसंबर को दो सौ से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इस बीच परिस्थितियों के मद्देनजर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। यही नहीं उसने किराये में अनापशनाप बढ़ोतरी की पेशगी रोकथाम के लिए 'कैप' की भी घोषणा की, जिसके तहत पांच सौ किमी तक रू. 7500/-, पांच सौ से एक हजार किमी तक रुपये 12000/- और अधिकम रू. 18,000/- की हद बांध दी।

हवाई यात्रा के इतिहास में इतने बुरे दिन कभी नहीं गुजरे थे, जितने बीतते साल में आखिरी महिने के पहले हफ्ते में बीते 7 भारत में हवाई-परिवहन में अग्रणी इंडिगो ने इतनी बड़ी तादाद में घरेलू उड़ानें रद्द कीं कि कोहराम मच गया। हवाई अड्डों पर बस अड्डों से भी बदतर दृश्य देखने को मिले। अव्यवस्था, अफरातफरी, आक्रोश, शिकायतें, क्रंदन, गालीगलौज़, बेबसी और हताशा के मिलेजुले इतने बड़े पैमाने पर पहले कभी न देखे गये मन-मस्तिष्क को झकझोर देने वाले दृश्य सामने आये। सरकार की हिदायत के बाद इंडिगो के सीईओ पीटर्स ने रविवार को यात्रियों को 610 करोड़ रुपये और तीन हजार से अधिक बैग लौटाने का ऐलान किया, लेकिन आलम यह था कि रविवार को भी 650 उड़ानें रद्द हुईं। और इससे पहले शनिवार को 1500 उड़ानें रद्द होने की खबर थी। जाहिर है कि घरेलू नागरिक उड्डयन लगभग ठप्प था। फलतः खामियाजा उन लाखों मुसाफिरों ने भुगता, जो हवाई यात्रा को निरापद, सुविधाजनक और त्वरित मानकर वरियता देते थे। बदइंतजामी का आलम यह था कि दिल्ली से सोमवार आठ दिसंबर को दो सौ से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इस बीच परिस्थितियों के मद्देनजर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। यही नहीं उसने किराये में अनापशनाप बढ़ोतरी की पेशगी रोकथाम के लिए 'कैप' की भी घोषणा की, जिसके तहत पांच सौ किमी तक रू. 7500/-, पांच सौ से एक हजार किमी तक रुपये 12000/- और अधिकम रू.18,000/- की हद बांध दी।

जो कुछ हुआ उसे बिला शक अभूतपूर्व संकट की ही संज्ञा दी जायेगी। अनुमान है कि करीब तीन लाख हवाई यात्रियों को तीन दिनों तक बंधकों सा बेचारगी का तकलीफदेह वक्त बिताना पड़ा। गंतव्य तक पहुंच नहीं पाने से बड़ी संख्या में लोग इलाज, इंटरव्यू, परीक्षा और शादी-ब्याह के अवसरों से वंचित रहे। मोटे तौर पर यह संकट पायलटों की कमी से पैदा हुआ। माना जाता है कि इंडिगो-प्रबंधन की अदूरदर्शिता और लेतलाली के चलते यह विषम स्थिति उत्पन्न हुई। पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम का यह कथन समीचीन है कि पायलट ड्यूटी की नियमावलि सरकार ने जनवरी, 24 में जारी कर दी थी, लेकिन विमानन कंपनी ने 23 माह की लंबी अवधि में कोई तैयारी नहीं की। चिदंबरम ने तंज करते हुये कहा कि मोहलत की परवाह न करने पर जब लाखों यात्री फँसे तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिये और उनकी कोई सुध नहीं ली। इंडिगो द्वारा सैकड़ों उड़ानों को रद्द करने से अभूतपूर्व और विकराल संकट उत्पत्ति होने का प्रमुख कारण यह है कि भारत में नागरिक उड्डयन में संप्रति इंडिगो का वर्चस्व है। घरेलू मार्केट में उसकी भागीदारी 65 प्रतिशत है, जबकि एयर इंडिया तथा अन्य का शेयर क्रमशः 30 और पांच फीसद है। घरेलू उड्डयन में इंडिगो का एकाधिकार पिछली दहाई की देन है। सन 2014 के घरेलू उड़ानों के परिदृश्य की बात करें तो इंडिगो की भागीदारी तब मात्र 30 प्रतिशत थी। तब एयरइंडिया और स्पाइस जेट 18-18 प्रतिशत, गो एयर नौ फीसद, जेट एयरवेज 21 फीसद, एयर एशिया एक फीसद और अन्य तीन फीसद भागीदारी रखते थे, लेकिन बीते दशक में इंडिगो ने खूब छलांगें भरी और देखते ही देखते अन्य एयरलाइन्स को विस्थापित कर घरेलू आसमान पर कब्ज़ा कर लिया। फर्ज कीजिये कि घरेलू विमानन का परिदृश्य एक दहाई पहले जैसा होता तो यकीनन वैकल्पिक उड़ानों की उपलब्धता के चलते विमान यात्रियों की इतने बड़े संकट का सामना नहीं करना पड़ता। प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि भारत में नागरिक विमानन का यथार्थ अमेरिका व विकसित राष्ट्रों से सर्वथा भिन्न है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या अन्य यूरोपीय देशों में किसी निजी एयरलाइंस का शेयर औसतन 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

इंडिगो निर्विवादतः आज भारत की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन है। यह प्रतिदिन करीब 2300 उड़ानें संचालित करती है। गत वर्ष लगभग 11.8 करोड़ यात्रियों ने इसमें उड़ान भरी थी। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड का यह उपक्रम सफलता के मान से अग्रणी है। इसके संस्थापक राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल हैं तथा इसका मुख्यालय हरियाणा में गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना सन् 2006 में हुई थी और इसने उसी वर्ष परिचालन भी प्रारंभ किया। कंपनी के 51 प्रतिशत स्टाक इंटरग्लोब और 48 प्रतिशत स्टाक गंगवाल की वर्जीनिया (यूएसए) स्थित कंपनी कैलम इंवेस्टमेंट्स के पास है। सन 2011 में इसे विदेशों में संचालन के लिए लाइसेंस मिला द्य इसने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा की शुरुआत सितंबर 2011 में दुबई-दिल्ली उड़ान से की। उल्लेखनीय बात यह है कि इसने प्रारंभिक दौर में प्रतिस्पर्धा में किंगफिशर को विस्थापित करने में कामयाबी पाई। इंटरग्लोब के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर और इंटरग्लोब एविएशन में प्रोमोटर तथा एमडी राहुल भाटिया के बिजनेस इंटरेस्ट ट्रैवल, होस्पिटैलिटि, लाजिस्टिक्स और टेक्नालाजी के इर्दगिर्द फैले हुए हैं। होस्पिटैलिटि में यह फ्रांसीसी दिग्गज एकार की सहयोगी है और दोनों भारत तथा विदेश में 30 से अधिक होटल संचालित करते हैं। इंडिगो गुरुग्राम में अपने कार्पोरेट दफ्तर के समीप एक रेस्त्रां भी चलाती है। राडार बॉक्स के मुताबिक आज इंडिगो विश्व में छठवीं व्यस्ततम एयर सेवा है। राहुल भाटिया और उनके उपक्रमों का नाम इलेक्टोरल-बॉन्ड्स से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने चार राजनीतिक दलों को 56 करोड़ रुपयों का बड़ा डोनेशन दिया था। उनके चंदे का बड़ा हिस्सा यानि करीब 31 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी के खाते में गये। तृणमूल कांग्रेस को 16.2 करोड़ रुपये, कांग्रेस को 5 करोड़ रुपये और एनसीपी को 3.8 करोड़ रुपये मिले। राहुल भाटिया ने स्वयं भी बीस करोड़ रुपये के बाँड खरीदे थे। सहज ही समझा जा सकता है कि उन्होंने सर्वाधिक किसको उपकृत किया? यह ज्ञात तथ्य है कि बॉन्डस वित्तीय और राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करते हैं और इनसे कारोबार में नफा-नुकसान तय होता है। इस बीच इस आशय की खबर आई है कि इंडिगो-संकट जान-बूझकर पैदा किया गया है।

इंडिगो के पास 4551 पायलट हैं द्य सिर्फ 124 पायलटों की कमी है। अतः 2200 में से केवल 5 से 7 प्रतिशत उड़ानें प्रभावित होनी थी, लेकिन षड्यंत्रपूर्वक बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसल की गयी। यदि ऐसा है तो संकट प्राकृतिक नहीं, इंजीनियर्ड था। यानि प्राफिट को तरजीह दी गयी। एयर- लाइन पायलट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सैम थॉमस का कहना है कि मुनाफे को सुरक्षा के ऊपर रखा जा रहा है। दो साल पहले घोषित नियमों को वापस करवाने के लिये इंडिगो ने इतना बड़ा खेल खेला। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, आपराधिक कृत्य है।

एक और सन्दर्भ जो इंडिगो-संकट के परिप्रेक्ष्य में उभर कर सामने आया है, यह है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 8 अक्टूबर, 25 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है और 25 दिसंबर से इंडिगो की नयी उड़ान सेवाओं के साथ यह उड़ान सेवाओं के लिए खुल जाएगा। लेकिन इस बीच इंडिगो के संकट से सारा गुड़ गोबर हो गया और मुमकिन है कि यह ऐलान टल जाए। इस बीच वैश्विक कारबार में धूमकेतु की तरह उभरे गौतम अदाणी उड्डयन के क्षेत्र में एंट्री कर चुके हैं। अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, लिमिटेड (एएएचएल) की स्थापना सन् 2019 में हो चुकी है। अडाणी ग्रुप ने अपना पहला कदम हवाई अड्डों में रखा है। उसने छह हवाई अड्डों-अहमदाबाद, लखनऊ, विशाखापतनम, मंगलूरू, जयपुर और गुवाहाटी स्थित हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास का जिम्मा लिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ उसका एतद् विषयक समझौता हो चुका है।

इंडिगो के जरिए उपजे संकट ने लोकसभा में प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चेतावनी को भी जेरे-बहस ला दिया है। राहुल ने तेरह माह पूर्व 'इंडियन एक्सप्रेस' में इस बारे में लेख लिखा था। 'मैच फिक्सिंग एकाधिकार बनाम निष्पक्ष व्यापार : डर पर स्वतंत्रता को चुनने का समय' शीर्षक लेख में उन्होंने आर्थिक एकाधिकार और उसके खतरों की ओर संकेत किया था। वक्त की कसौटी पर उनकी चेतावनी खरी उतरी। इंडिगो - संकट ने आशंकाओं का कद बढ़ा दिया है। यह लांछन अपनी जगह है कि सरकार ने हवाई यात्रियों के हितों की रक्षा नहीं की द्य वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन प्रश्न करते हैं कि आपदा प्रबंधन से एयरफोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, जबकि उसके पास सी 17 ग्लोबमास्टर और सी 130 सुपर हरकुलस हेलीकाप्टरों समेत छह बोइंग 737 का बेड़ा मौजूद है। इस बीच एक बड़ी और दूरगामी महत्त्व की घटना यह घटी है कि अडाणी समूह ने 820 करोड़ रुपयों में फ्लाइट ट्रेनिंग कंपनी फ्लाइट स्टीमुलेशन टेक्नीक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (एफएसटी) खरीद ली है। आगामी समय में हवाई यातायात बढ़ेगा और नया हवाई बेड़ा भी जुड़ेगा। अनुमान है कि 1500 से अधिक एयरक्राफ्ट हवाई परिदृश्य में पदार्पण करेंगे। जाहिर है कि उन्हें उड़ाने के लिए कुशल पायलट चाहिए और एफएसटी पायलटों के प्रशिक्षण की सबसे बड़ी इकाई है। तो क्या इंडिगो-संकट एक नये बदलाव की पूर्व पीठिका साबित होगा?

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

लेखक स्तंभकार हैं।

बिहार: बेलगाम अपराधों का बढ़ता साया

बिहार में नई सरकार के गठन को अभी अधिक समय नहीं हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से अपराध की घटनाएँ सामने आ रही हैं, उसने राज्य में एक बार फिर कानून-व्यवस्था की स्थिति को कठघरे में खड़ा कर दिया है। चुनावी मंचों से बार-बार यह दावा किया गया था कि बिहार अब अपराधमुक्त होगा, जंगलराज अतीत की बात हो चुका है, और नई सरकार अपराधियों पर ऐसा शिकंजा कसेगी कि वे खुद राज्य छोड़कर भागेंगे। मगर सत्ता संभालते ही कुछ ही हफ्तों में जिस तरह की घटनाएँ घटी हैं, उन्होंने इन दावों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। ऐसा लगता है कि राज्य में प्रशासनिक तंत्र कमजोर पड़ रहा है और अपराधी खुलेआम अपनी मनमरज़ी करने लगे हैं। कानून का भय, जो किसी भी राज्य की शांति और स्थिरता का आधार होता है, वह लगातार क्षीण होता दिखाई दे रहा है। अररिया में एक युवा शिक्षिका की दिनदहाड़े हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक महिला, जो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर बच्चों को पढ़ाने विद्यालय जा रही थी, उसे बीच सड़क पर रोककर गोली मार दी गई। न केवल यह घटना अपने आप में भयावह है, बल्कि यह तथ्य कि शिक्षिका को लगातार धमकियाँ मिल रही थीं, राज्य की कानून-व्यवस्था पर और भी गहरे सवाल उठाता है। जब एक शिक्षिका जिसे समाज का दीपक माना जाता है, खुद अपनी सुरक्षा के लिए असुरक्षित महसूस करे, तो यह समझना कठिन नहीं कि आम लोगों के मन में किस हद तक दहशत व्याप्त होगी।

नीतीश कुमार की सरकार हमेशा से खुद को महिला हितैषी बताती आई है। साइकिल योजना से लेकर कन्या उत्थान कार्यक्रमों तक, महिलाओं के उत्थान और सुरक्षा को उसकी प्राथमिकता बताया जाता रहा है। लेकिन जब धरातल पर महिलाओं की सुरक्षा ही लगातार सवालों के घेरे में हो, जब महिलाएँ सड़कों पर दिनदहाड़े निशाना बन रही हों, और जब अपराधी लगातार प्रशासन की नाक के नीचे वारदातों को अंजाम दे रहे हों, तब ऐसे दावों की विश्वसनीयता खुद ही ढहने लगती है। राज्य के नए गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने कुछ दिन पहले कहा था कि 'बिहार अपराधियों के लिए नहीं है, और अपराधियों को राज्य छोड़कर जाना होगा।' परंतु अपराधियों की वर्तमान गतिविधियाँ इस बयान का खुला मज़ाक उड़ाती प्रतीत होती हैं। पिछले पंद्रह दिनों में ही बिहार में पैंतालीस से अधिक हत्याएँ दर्ज की गईं, यह आँकड़ा दिखाता है कि अपराधी किस हद तक निडर हो चुके हैं। चाहे पटना हो या गया, सीवान हो या मुजफ्फरपुर, अररिया हो या भागलपुर, हर जगह अपराधियों ने पुलिस-प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी कर दी है।

राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान जिस 'जंगलराज' का हवाला देकर जनता को चेताया था, वही जंगलराज अब नए रूप में सिर उठाता दिख रहा है। अपराध का ग्राफ जिस तेजी से ऊपर जा रहा है, वह यह संकेत देता है कि प्रशासनिक ढाँचे में कुछ न कुछ बहुत गंभीर खामी है। पुलिस बल का कमजोर मनोबल, खुफिया तंत्र का असफल होना, राजनीतिक संरक्षण की सम्भावनाएँ और त्वरित कार्रवाई का अभाव- ये सभी कारण अपराधियों को और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं।बिहार में अपराध की समस्या नई नहीं है। लंबे समय तक राज्य अपहरण उद्योग, रंगदारी और गैंगवार के लिए बदनाम रहा। लेकिन पिछले दो दशकों में कुछ सुधार देखने को मिले थे। कानून का शासन मजबूत हुआ था, और आम लोगों में यह भरोसा पैदा हुआ था कि अपराधी चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। यही कारण था कि सुशासन का नारा बिहार की राजनीति में लंबे समय तक प्रभावी रहा। लेकिन आज जब उसी सुशासन की बात करने वाली सरकार पर ही अपराध रोक पाने में असफल रहने का आरोप लग रहा है, तो यह स्थिति और भी चिंताजनक बन जाती है।

अपराध की बेलगाम बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो प्रशासनिक मशीनरी का सक्रिय न होना या उसका समय पर प्रतिक्रिया न देना। अपराध की घटनाओं के बाद अक्सर कार्रवाई की बातें तो खूब सुनाई देती हैं, लेकिन अपराधियों की धर-पकड़ में वह तत्परता नजर नहीं आती, जो एक मजबूत प्रशासन की पहचान होती है। दूसरा कारण राजनीतिक हस्तक्षेप का हो सकता है। कई बार स्थानीय स्तर पर

राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान जिस 'जंगलराज' का हवाला देकर जनता को चेताया था, वही जंगलराज अब नए रूप में सिर उठाता दिख रहा है। अपराध का ग्राफ जिस तेजी से ऊपर जा रहा है, वह यह संकेत देता है कि प्रशासनिक ढाँचे में कुछ न कुछ बहुत गंभीर खामी है। पुलिस बल का कमजोर मनोबल, खुफिया तंत्र का असफल होना, राजनीतिक संरक्षण की सम्भावनाएँ और त्वरित कार्रवाई का अभाव- ये सभी कारण अपराधियों को और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। बिहार में अपराध की समस्या नई नहीं है। लंबे समय तक राज्य अपहरण उद्योग, रंगदारी और गैंगवार के लिए बदनाम रहा। लेकिन पिछले दो दशकों में कुछ सुधार देखने को मिले थे।

अपराधियों को संरक्षण मिलता है, जिससे कानून-व्यवस्था और भी कमजोर होती है। तीसरा कारण पुलिस बल की कमी और संसाधनों की सीमितता है। जब एक पुलिसकर्मी पर अत्यधिक भार हो, जब चौकसी उचित स्तर पर न हो, जब तकनीकी संसाधनों की कमी हो, तो अपराधी स्वाभाविक रूप से साहसिक होते जाते हैं। परंतु अपराध की समस्या केवल पुलिस और प्रशासन की विफलता का परिणाम नहीं होती। यह सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कार और शासन की संवेदनशीलता का भी दर्पण होती है। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों और व्यक्तिगत वफादारियों पर टिकी रही है। अपराधी अक्सर इन समीकरणों का फायदा उठाते हैं- कभी किसी जातीय समूह का समर्थन लेकर, कभी किसी स्थानीय नेता की कृपा से। ऐसे में यह जरूरी है कि सत्ताधारी दल कानून-व्यवस्था को राजनीतिक चश्मे से न देखकर, केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखे।

आज जरूरत इस बात की है कि अपराध को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की जाए। केवल बयानबाजी से अपराध रुकने वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन को आधुनिक तकनीकों से लैस करना होगा, उनकी संख्या बढ़ानी होगी, और साथ ही उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। खुफिया तंत्र को मजबूत करना होगा, ताकि अपराध होने से पहले ही उसका सुराग मिल सके। त्वरित कार्रवाई, फास्ट-ट्रैक अदालतें और दोषियों को कठोर सजा- ये सभी कदम मिलकर अपराध के बढ़ते ग्राफ को रोक सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पहल जरूरी है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ी है, वहाँ उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखना आवश्यक है। स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, ग्रामीण इलाकों की महिलाओं- सभी के लिए सुरक्षित वातावरण राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। अररिया की शिक्षिका की हत्या केवल कानून-व्यवस्था की असफलता नहीं, बल्कि महिला सम्मान पर सीधा प्रहार है। यह घटना याद दिलाती है कि अगर समाज के सबसे संवेदनशील और जिम्मेदार वर्ग शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित न हो सके, तो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे गारंटी की जा सकती है?

चुनावों के दौरान विपक्ष पर जंगलराज का आरोप लगाने वाले दल आज सत्ता में हैं। इसलिए यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपराध की हर एक घटना पर संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया दें, न कि केवल औपचारिक बयान जारी करें। जनता ने उन्हें सुरक्षा और स्थिरता के वादे पर वोट दिया है। यदि अपराध इसी गति से बढ़ता रहा, तो जनता का विश्वास डगमगाने लगेगा। लोकतंत्र में सरकार की विश्वसनीयता ही उसकी सबसे बड़ी पूँजी होती है, और बेलगाम अपराध उस पूँजी को क्षय कर देता है। बिहार को एक बार फिर उस मोड़ पर नहीं पहुँचना चाहिए, जहाँ लोगों को रात में घर से निकलने से डर लगे, जहाँ कारोबारियों को रंगदारी और डर के साए में रहना पड़े, जहाँ महिलाएँ खुद को असुरक्षित महसूस करें और जहाँ युवा, विकास के बजाय हिंसा और भय की छाया में अपने सपने दम तोड़ दें। एक राज्य तभी प्रगति कर सकता है जब वह अपने नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दे सके। कानून-व्यवस्था किसी भी सरकार का आधार स्तंभ होता है; अगर वही चरमराने लगे, तो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सब कुछ प्रभावित होता है।

इसलिए अब वक्त है कि बिहार सरकार बेलगाम अपराध पर कठोर कदम उठाए। अपराधियों को यह स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि राज्य में कानून सर्वोपरि है और किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केवल राजनीतिक बयान, उद्घाटन भाषण और धरातल से कटे वादों से नहीं, बल्कि वास्तविक कठोर कार्रवाई से ही बिहार फिर से सुशासन की राह पर लौट सकता है। जनता की सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है, और अगर इसमें ही चूक हो रही है, तो शासन की पूरी इमारत डगमगाने लगती है। बिहार के लोगों को भयमुक्त जीवन चाहिए, न कि दहशत और असुरक्षा की वह छाया, जिसे वे अतीत में एक बार झेल चुके हैं। बिहार का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब वर्तमान में कानून-व्यवस्था दुरुस्त हो। अपराधियों पर नकेल कसना, पुलिस को मजबूत करना, प्रशासन को जवाबदेह बनाना और समाज के प्रति संवेदनशील शासन की स्थापना, यही वे कदम हैं जिनसे राज्य एक बार फिर विश्वास की उस राह पर लौट सकता है, जहाँ नागरिक बेखौफ होकर अपनी जिंदगी और सपनों को जी सकें।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अग्निबाण पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

बदलाव

डॉ. मनीष जैसल

लेखक स्तंभकार हैं।

श्रम संहिता में श्रमिकों के लिए क्या है?

भारत में श्रम सुधारों को लेकर लंबे समय से चर्चा है कि श्रम कानून अत्यधिक जटिल और बिखरे हुए हैं तथा उन्हें व्यावहारिक रूप से लागू करना कठिन हैं। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने 2019 और 2020 के बीच 29 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर उन्हें चार नई श्रम संहिताओं, वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता में समेकित किया है । सरकार का दावा है कि यह स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा श्रम सुधार है, जो श्रमिकों को सुरक्षा और उद्योगों को गति प्रदान करेगा।

सरकार कहती है कि नई श्रम संहिताएँ न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान, समान कार्य पर समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत करेंगी। दावा यह भी है कि गिग वर्कर्स, फिक्स-टर्म कर्मचारी और महिलाओं को समान सुरक्षा मिलेगी तथा ग्रेच्युटी के लिए न्यूनतम अवधि पाँच वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई है। यह चर्चा भी है कि इससे नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योगों के लिए विनियमन आसान होगा। देखने और सुनने में यह सब आधुनिक और श्रमिक-हितैषी लगता है।

लेकिन वास्तविकता हमेशा दावों जैसी सरल नहीं होती। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि नई औद्योगिक संबंध संहिता के तहत उद्योगों के लिए हायर एंड फायर अर्थात् नियुक्ति व छंटनी की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान हो गई है। इससे रोजगार की स्थिरता कम होने की आशंका है। जब कंपनियाँ स्थायी कर्मचारियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स-टर्म मॉडल अपनाएंगी, तो सामाजिक सुरक्षा का लाभ व्यवहार में कमजोर पड़ सकता है। और यदि नौकरी टिकाऊ नहीं रहेगी, तो वेतन, पेंशन, बोनस या बीमा, सबके वादे अधूरे रह जाएंगे। भारत की कुल श्रम शक्ति लगभग 50 करोड़ है, जिनमें से करीब 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। 2015 में सामाजिक सुरक्षा का कवरेज मात्र 19 प्रतिशत था। हालिया ILO रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक यह कवरेज 64.3 प्रतिशत तक बढ़ने का दावा किया गया है, जिससे 94 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है।

नई संहिताओं का सबसे संवेदनशील असर सफाई कर्मचारियों, तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो देश की सेवा प्रणाली की रीढ़ हैं। अस्पतालों, पंचायतों, नगर निगमों, विश्वविद्यालयों, रेलवे स्टेशनों और तमाम सरकारी व निजी संस्थानों में ये लोग सबसे ज्यादा श्रम करते हैं, परन्तु न्यूनतम वेतन, बीमा, सुरक्षा उपकरण और सम्मान इनमें से अधिकांश से वंचित रहते हैं। नई संहिताएँ उनके लिए सुरक्षा और न्यूनतम वेतन का वादा करती हैं, लेकिन यदि अधिकांश संस्थान उन्हें ठेका-प्रणाली के अंतर्गत रखेंगे, तो इन लाभों का वास्तविक कार्यान्वयन संदिग्ध हो जाएगा। पहले ही कई नगर निगमों में स्वच्छता कर्मी 8-10 घंटे काम करते हुए भी न्यूनतम वेतन तक नहीं पाते, और ठेकेदारों के शोषण का शिकार होते हैं। यदि श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन सख्त नहीं होगा, तो यह वर्ग सबसे पहले मार झेलेगा।

दूसरी ओर, आवश्यकता यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और स्वच्छता योद्धाओं को न्यूनतम वेतन से आगे 'सम्मानजनक वेतन', सुरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य बीमा, कार्य-स्थल असुरक्षा से सुरक्षा और नियमित नियुक्ति मिले। इन श्रमिकों के बिना कोई भी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल या नगर व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रह सकता। इसलिए ज़रूरी है कि श्रम संहिता इन्हें 'क़ानूनी मजबूरी' के आधार पर नहीं, बल्कि 'राष्ट्र निर्माता' के रूप में सुरक्षा दे। यदि ये नई संहिताएँ उनकी गरिमा नहीं बढ़ातीं, तो सुधार का अर्थ आधा-अधूरा रह जाएगा।

ट्रेड यूनियनों की शक्ति और सामूहिक सौदेबाजी अधिकारों की सीमाएँ भी चिंता का विषय हैं। हड़ताल और सामूहिक आवाज़ पर बढ़ते कानूनी नियंत्रण से श्रमिकों के अधिकार कमजोर होने का खतरा है।

इस सबके बीच यह स्वीकार करना चाहिए कि श्रम सुधारों की आवश्यकता थी और 29 अलग-अलग कानूनों को एकीकृत करना निश्चित रूप से साहसिक कदम है। लेकिन सुधारों का मूल्यांकन नारेबाज़ी या सरकारी विज्ञापन के आधार पर नहीं, बल्कि श्रमिक के जीवन में आए वास्तविक बदलाव से किया जाएगा। यदि ये संहिताएँ श्रमिकों को स्थिरता, सुरक्षा, सम्मान और न्याय नहीं दे पातीं, तो यह सुधार अधूरा ही कहलाएगा।

ये चार श्रम संहिताएँ केवल क़ानूनी संरचनाएँ नहीं, बल्कि भारत की श्रम-सभ्यता के भविष्य की दिशा हैं। प्रश्न यह नहीं कि सुधार ऐतिहासिक हैं या नहीं, वास्तविक प्रश्न यह है कि यह सुधार किनके लिए ऐतिहासिक सिद्ध होंगे? श्रमिकों के लिए या उद्योगों के लिए?

विश्व मानवाधिकार दिवस

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

सुरक्षित बचपन की दिशा में भारत का भविष्य

भारत बीसवीं सदी के अंत से अब तक दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन एक सच ऐसा भी है, जो अब भी विकास की चमक के नीचे दबा है सामाजिक रूढ़ि के तौर पर बाल विवाह। पचास वर्षों में जरूर इस कुप्रथा की दर आधी हुई है, पर यूनिसेफ के नवीनतम आँकड़े बताते हैं कि दुनिया की हर तीसरी बाल वधू आज भी भारत में ही मिलती है। हर वर्ष लगभग 15 से 18 लाख किशोरियाँ बाल विवाह के दायरे में शामिल हो जाती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वे-5 के अनुसार 23.3 फीसदी भारतीय लड़कियाँ अठारह वर्ष से पहले ही विवाहबद्ध कर दी जाती हैं। यह वह समाज है जो 'बेटियों की पूजा' की घोषणा करता है, पर वास्तविकता यह है कि लड़कियों को आज भी उनके बचपन और अधिकारों से वंचित करने वाली परंपराएँ आसानी से सामाजिक स्वीकार्यता पा जाती हैं।

यह समस्या अक्सर केवल ग्रामीण पिछड़ेपन या अशिक्षा से जोड़कर देखी जाती है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं गहरी हैं। यह हमारे सामाजिक अवचेतन में मौजूद उस मानसिकता का परिणाम है जिसने परंपरा, सम्मान और सुरक्षा को बच्चों की आज़ादी और भविष्य से बड़ा मान लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम जैसे राज्य आज भी राष्ट्रीय औसत से कहीं ऊपर हैं। जहाँ भी लड़कियाँ माध्यमिक शिक्षा में नहीं पहुँच पातीं, वहाँ बाल विवाह की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। स्कूल की देहरी से दूरी ही कई बार विवाह की देहरी तक पहुँचने का पहला कदम बन जाती है।

कम उम्र में गर्भधारण से लेकर मातृ मृत्यु दर और कुपोषित बच्चों के जन्म तक, बाल विवाह सिर्फ सामाजिक कुरीति नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और मानवाधिकार तीनों पर सीधा आघात है। लड़कियाँ शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की क्षमता से वंचित हो जाती हैं, और देश उस जनसंख्या लाभ से भी हाथ धो बैठता है, जो युवतियों की सक्रिय भागीदारी से संभव हो सकता था। विकास की गति पर इस बोझ का असर साफ़ दिखता है, पर समाज की जड़ता आँकड़ों से अक्सर बड़ी सिद्ध होती है।

इसी जड़ता को चुनौती देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 'बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम' की शुरुआत की। यह कार्यक्रम केवल कानून पर आधारित कार्रवाई भर नहीं, बल्कि समाज के मनोविज्ञान से लड़ने वाली पहल है। भारत में किसी भी कुरीति के उन्मूलन में कानून की सफलता तभी संभव होती है जब समाज अपने व्यवहार और मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हो। अब तक की स्थिति यही बताती है कि परिवर्तन की दिशा तय हो चुकी है, पर उसकी गति उस समस्या की व्यापकता के सामने बेहद धीमी है।

भारत का सामाजिक इतिहास देखें तो कई रूढ़ियाँ दहेज, परदा, बेटी को बोझ समझना, परिवार की इज़्ज़त को लड़की के शरीर से जोड़ देना सदियों तक लोगों के जीवन का हिस्सा बनी रहीं। बाल विवाह इन सबके बीच सबसे पुरानी, सबसे सूक्ष्म और सबसे घातक कड़ी रही है। यह वह प्रथा है, जो बचपन को चुपचाप विदा कर देती है और लड़की का भविष्य विवाह की देहरी पर ही बाँध देती है। कई बार तो परिवारों को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वे परंपरा निभाने के नाम पर बच्चे से उसका संपूर्ण जीवन छीन रहे हैं।

फिर भी, ठीक इसी देश में पिछले पचास वर्षों में बदलाव की धीमी लेकिन स्थिर यात्रा भी दिखाई देती है। शिक्षा के फैलाव, महिला समूहों, मीडिया, न्यायपालिका और सरकारी पहलों ने मिलकर उन मान्यताओं को चुनौती दी है जिन्हें कभी अटूट माना जाता था। जो समाज कभी विवाह को ही लड़की की 'एकमात्र सुरक्षा' मानता था, वह धीरे-धीरे यह समझने लगा है कि सुरक्षा शिक्षा से आती है, सम्मान अवसरों से, और भविष्य तभी बनता है जब बचपन को बचने दिया जाए।

अगर इतिहास के पन्नों से शुरू करें, तो 1970-80 के दशकों में भारत के कई ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह को लगभग स्वीकृत सामाजिक नियम माना जाता था। आधे से अधिक लड़कियाँ, कई राज्यों में तो 60 प्रतिशत तक, अठारह वर्ष पूरे होने से पहले ही विवाहबद्ध कर दी जाती थीं। कानून थे, पर उनकी भूमिका प्रतीकात्मक थी। बेटी का जन्म ही चिंता का

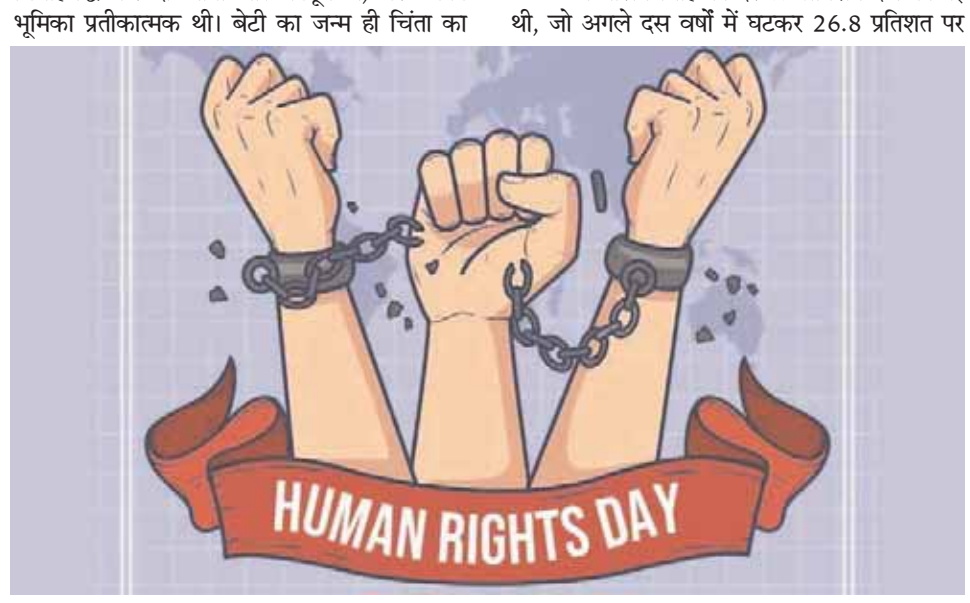

पिटारा समझा जाता था दहेज से लेकर सुरक्षा तक और जल्दी विवाह ही इन चिंताओं का तथाकथित समाधान माना जाता था। सामाजिक दबाव इतना अधिक था कि इस प्रथा पर सवाल उठाना लगभग असंभव था।

1990 के दशक में जब शिक्षा अभियानों और महिला समूहों की पहुँच गाँव-गाँव तक पहुँची, तब पहली बार बाल विवाह को सामाजिक आलोचना के दायरे में जगह मिली। 1998-99 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण बताते हैं कि उस समय भी लगभग 50 प्रतिशत किशोरियाँ कानूनन उम्र से पहले विवाह कर दी जाती थीं। बदलाव की आवाज़ें थीं, पर दबी हुई। प्रयास हो रहे थे, पर उन्हें संगठित रूप का अभाव था।

नई सदी ने स्थिति को अधिक निर्णायक मोड़ दिया। 2000 से 2010 के बीच शिक्षा अभियानों, जनचेतना कार्यक्रमों और सरकारी प्रोत्साहनों ने बाल विवाह को एक व्यक्तिगत निर्णय से उठाकर राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। 2006 में बाल विवाह की दर 47 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जो अगले दस वर्षों में घटकर 26.8 प्रतिशत पर आ गई। पहली बार स्पष्ट हुआ कि जब लड़कियाँ स्कूल में टिकती हैं, तो विवाह स्वतः टलता है; और जब परिवारों को आर्थिक व सामाजिक प्रोत्साहन मिलता है, तो वे निर्णयों को बदलने को तैयार होते हैं।

फिर भी, मौजूदा तस्वीर उतनी उत्साहजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक बाल वधुओं वाला राज्य है। उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आते हैं। यहाँ गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक दबाव आज भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बाल विवाह का स्वरूप भी बदला है अब कई विवाह मंदिरों में, देर रात, सीमित गवाहों के बीच, या डिजिटल निमंत्रणों के जरिए सम्पन्न किए जाते हैं ताकि कानून की निगाह से बचा जा सके।

ऐसे समय में 'बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम' परिवर्तन की दिशा में एक अहम कदम है। इसकी बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने बाल विवाह को किसी एक विभाग की जिम्मेदारी न मानकर पूरे शासन तंत्र की साझी ज़िम्मेदारी बनाया है। स्कूल, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, पंचायत, न्यायपालिका और समुदाय-सबको इस अभियान का सक्रिय भागीदार बनाया गया है। कई जिलों ने जोखिम सूची तैयार की, स्कूल ड्रॉपआउट को लाल-श्रेणी में चिन्हित किया, और समय रहते हस्तक्षेप कर विवाह रोके। इससे रिपोर्टिंग की संस्कृति में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब पहले की तरह बाल विवाह को परिवार का 'निजी मामला' मानकर चुप्पी नहीं साधी जाती। पड़ोसी, रिश्तेदार, शिक्षक और स्वयं किशोर–सब आगे आकर रोकथाम की सूचना देने लगे हैं। यह मनोवैज्ञानिक बदलाव इस कुप्रथा की सामाजिक स्वीकार्यता के कमजोर पड़ने का संकेत है।

इस अभियान का केंद्र लड़कियों की शिक्षा को बनाया गया है। अनुभव बताता है कि छात्रवृत्ति, साइकिल योजनाएँ, परिवहन और सुरक्षा उपायों ने कई जिलों में बड़ा फर्क डाला है। शिक्षा ने लड़कियों को आवाज़ दी है और परिवारों के सामने एक वैकल्पिक भविष्य रखा है वह भविष्य जो कभी उन्हें असंभव लगता था।

प्रश्न केवल कानून का नहीं, सामाजिक चेतना और सामूहिक ज़िम्मेदारी का है। अगर भारत सचमुच बाल विवाह मुक्त समाज बनना चाहता है, तो अगले दशक को शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक अवसरों और जन-जागरूकता पर केंद्रित करना होगा। हर परिवार को यह समझना होगा कि बाल विवाह संरक्षण नहीं, अन्याय है; और हर लड़की सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की शक्ति है। भारत ने इस दिशा में यात्रा शुरू कर दी है। अब ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि यह यात्रा न रुके, न थमे और आने वाली पीढ़ियों तक लगातार चलती रहे।

विश्व मानवाधिकार दिवस पर विशेष

योगेश कुमार गोयल

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के 77 वर्ष

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की विस्तृत व्याख्या के लिए 27 जनवरी 1947 को एक आयोग गठित किया गया था, जिसकी सिफारिशों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने 10 दिसम्बर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। तभी से विश्वभर में 10 दिसम्बर का दिन 'विश्व मानवाधिकार दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है। मनुष्य के जीवनयापन और विकसित होने के मूलभूत (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक) अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'मानवाधिकार' के रूप में स्वीकार किया गया है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि भविष्य में द्वितीय विश्वयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के कुछ ही समय बाद मानवाधिकारों का संरक्षण किए जाने की ओर ध्यान देना शुरू किया लेकिन विडम्बना है कि मानवाधिकारों की घोषणा के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी विश्वभर में करोड़ों लोग संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानवाधिकारों से वंचित हैं। करोड़ों लोग रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं। एक अरब से भी ज्यादा लोग कम अथवा ज्यादा कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण के कारण प्रतिदिन हजारों बच्चे काल के ग्रास बन रहे हैं। दुनियाभर में करोड़ों बच्चे बाल मजदूरी का दंश झेल रहे हैं। भारत में 8 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे अपने मासूम बचपन को बाल मजदूरी की तपती भट्ठी में झोंकने को विवश हैं, जो स्कूली शिक्षा से भी वंचित हैं। औद्योगिकीकरण की अंधी दौड़ में देश में मजदूर महिलाओं व छोटे-छोटे मासूम बच्चों का शारीरिक व मानसिक शोषण किसी से छिपा नहीं है। दुनियाभर में अरबों लोग आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हैं। एक अरब से अधिक लोगों को पीने के लिए स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हैं।

इसकी विवेचना यदि हम मानवाधिकारों की दृष्टि से करें तो क्या ये सभी उचित स्तर पर जीवनयापन के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, जीवन के प्रति सुरक्षा के अधिकार, शोषण से मुक्ति के अधिकार तथा अन्य सामाजिक अधिकारों से पूर्णतया वंचित नहीं हैं? क्या यह सरासर मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं है? क्या यह मानवाधिकार आयोग का दायित्व नहीं है कि वह इन विसंगतियों को दूर करने के लिए सार्थक एवं प्रभावी कदम उठाए? आधुनिक भारत में करोड़ों लोग आज भी भूखे-नंगे अपनी जिंदगी के दिन जैसे-तैसे उद्देश्यहीन पूरे कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए मानवाधिकारों का कोई महत्व हो सकता है? मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के अलावा लगभग प्रत्येक देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सक्रिय हैं लेकिन जिस गति से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उससे मानवाधिकार आयोगों के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगता है। दुनियाभर में दो प्रमुख मानवाधिकार संगठनों 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' व 'ह्यूमन राइट वाच' का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जो वैश्विक स्थिति पर नजर रखते हैं और प्रतिवर्ष इस पर अपनी रिपोर्ट भी पेश करते हैं। मानवाधिकार हनन के मामले में हर देश की क्रमानुसार स्थिति दर्शायी जाती है और इस रिपोर्ट के आधार पर जिस देश में मानवाधिकार की स्थिति दयनीय होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल आलोचना का शिकार होना पड़ता है बल्कि अमेरिका जैसे विकसित देश उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लाद देते हैं लेकिन वास्तविकता यही है कि पिछले कुछ वर्षों से इन संगठनों

की रिपोर्टों को भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं माना जाता। इन रिपोर्टों के पीछे अमेरिका इत्यादि विकसित देशों के अपने निजी हित या स्वार्थ भी छिपे होते हैं।

भारत में मानवाधिकार संगठनों की सक्रियता खासतौर से पंजाब के आतंकवाद के भयावह दौर से देखी जा रही है, जब इन संगठनों को पुलिस व सेना के जवानों का हर छोटा-बड़ा कारनामा तो नजर आता था लेकिन आतंकवादियों की करतूतों के विरूद्ध इनकी जुबान पर लगाम कसी रहती थी। इस बारे में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ए.एस. आनंद ने एक बार कठोर टिप्पणी करते हुए कहा भी था कि ये संगठन सुरक्षा बलों के अत्याचारों पर तो उंगली उठाते हैं पर आतंकवादी संगठन कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं, उस पर चुप रहते हैं। यह हकीकत भी है कि यदि कोई आतंकवादी या शरारती तत्व पुलिस अथवा सेना के हाथों मारे जाएं तो मानवाधिकारवादी संगठन खूब हो-हल्ला मचाते हैं लेकिन वहीं अगर यही सिरफिरे लोग निर्दोषों के लहू से होली खेलें, अबलाओं की इज्जत के सरेआम चिथड़े उड़ाएं, उन्हें गैंगरेप जैसी पाशविक घटनाओं को अंजाम देकर जिंदा जला डालें तो ऐसी हैवानियत मानवाधिकार के ठेकेदारों को नजर नहीं आती बल्कि ऐसे मामलों में इन संगठनों की भूमिका पर सवाल उठाने वालों के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि आतंकवादी संगठन किसी स्थापित कानून के तहत काम करने वाली कोई सरकारी संस्था नहीं हैं और वैसे भी आतंकवादी संगठनों की कार्रवाई चूंकि कानून की नजर में अपराध है, अतः यदि कोई आतंकवादी या अराजक तत्व पकड़ा भी जाए, तब उसके खिलाफ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होनी चाहिए।

हालांकि ऐसा नहीं है कि मानवाधिकार संगठनों की भूमिका हर मामले में ही संदेहास्पद रही हो बल्कि कई मामलों में इन संगठनों ने सही मायनों में पीड़ित मानवता के हित में सार्थक पहल की है किन्तु यह भी कटु सत्य है कि दुनियाभर में आज भी करोड़ों-अरबों लोग मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के 77 वर्षों बाद भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए 1961 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनियाभर में करीब 120 देशों में मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है। भारत में सितम्बर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य मानवाधिकारों का संरक्षण करना और उनको प्रोत्साहन देना ही था। आयोग के गठन के कुछ ही समय बाद आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि देश की सभी जटिलताओं को दृष्टिगत रखते हुए आयोग मानता है कि जो लोग सर्वाधिक दुर्बल हैं, उनके रक्षण का आयोग पर एक विशेष और अपरिहार्य दायित्व है लेकिन आयोग अपने गठन के बाद के इन 32 वर्षों में भी अपने दायित्वों को निभाने में कितना सफल रहा है, इसकी पड़ताल किए जाने की आवश्यकता है। यह विडम्बना ही है कि देश की सुरक्षा के नाम पर सुरक्षातंत्र को मजबूत करने व सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक हथियारों व उपकरणों की खरीद-फरोख्त के लिए तो हमारी सरकारें विभिन्न माध्यमों से चंद दिनों में ही अरबों रुपये जुटा सकती हैं लेकिन जब बात आती है राष्ट्र को निर्धनता, कुपोषण और भुखमरी के घोर अभिशाप से मुक्ति दिलाने की तो सारे सरकारी खजाने खाली हो जाते हैं। यदि इस दिशा में कभी कुछ करने का प्रयास किया भी जाता है तो ऐसी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने से पहले ही उनका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कर्णधार और नौकरशाह डकार जाते हैं। ऐसे में केवल मानवाधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन का ढ़ोल पीटने रहने से ही आखिर दुनिया को क्या हासिल हो रहा है?

योग साधना - 1

कर्मयोगी

(वरिष्ठ पत्रकार और योग जानकार)

हिमालय के सम्मोहन में विदेशी योगनियां

सिंगथाली के सुरम्य प्राकृतिक अधिवास में गंगा का सानिध्य विदेशी योग साधकों को भावविभोर करता है। उत्तराखंड की प्राकृतिक आभा मंत्रमुग्ध करती है। इस योग पर्व में उन्होंने योग के विभिन्न आयामों से रूबरू होने का अवसर पाया और इसका भरपूर लाभ भी उठाया। प्रातः कालीन सत्र में आसन, प्राणायाम व ध्यान, दिन में योग जिज्ञासाओं पर मंथन और रात्रि के सत्रों में योग के बौद्धिक विमर्श में इन विदेशी मेहमानों ने सक्रिय भागीदारी निभायी। इन विदेशी साधकों की योग जिज्ञासाओं के निराकरण के लिये कई विशेष सत्र भी इस दौरान आयोजित किए गए। वहीं गंगा के तट पर रोज होने वाला सांध्यकालीन गंगा आरती का आयोजन इन साधकों के लिये एक पर्व जैसा होता था। घाटी की गहराई में पहाड़ी इलाका होने के कारण सूर्य जल्दी ही ओझल हो जाता है। ऐसे में आरती में प्रयुक्त होने वाली कई ज्योति वाली दीप माला इन विदेशी मेहमानों के अंतर्मन को भिगो जाती थी। इसके बाद वे फिर अपनी योग साधनाओं में गहरे उतर जाते।

ऐसे दौर में जब लाखों भारतीयों के लिये पश्चिमी भोग संस्कृति के सम्मोहन और मौज-मस्ती के लिये विदेश जाना जुनून बना हुआ है, सैकड़ों विदेशी शांति-सुकून व आध्यात्मिक ज्ञान के लिये भारत का रुख कर रहे हैं। जिन पश्चिमी जीवन मूल्यों को आज भारतीय सुख के मानक मानकर अपनाने की होड़ में शामिल हैं, उससे उपजे मनोकायिक रोगों से मुक्ति के लिये विदेशी योगी-योगनियां हिमालय की शरण में आ रहे हैं। वे विदेशी अपने जीवन में कामयाब हैं। उनके पास संसाधनों व पैसे की कमी नहीं है। दरअसल, ये अमीर व विकसित देशों के लोग मशीनी होती जिंदगी की ऊब से मुक्त होने के लिए भारत आते हैं। योग नगरी ऋषिकेश तथा अन्य हिमालयी राज्यों के रमणीय स्थल इन विदेशियों की पसंदीदा जगह बने हुए हैं।

विश्व स्तर पर चर्चित योग नगरी ऋषिकेश में पूरे साल विदेशी योगियों व आध्यात्मिक शांति के चाहने वालों का तांता लगा रहता है। साल भर योग से जुड़े तमाम आयोजन होते रहते हैं। हाल ही में उत्तराखंड स्थित ऋषिकेश से कोई चालीस किलोमीटर की दूरी पर टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आने वाले सिंगथाली गांव के निकट बड़ी संख्या में विदेशी योगिनियों का हुजूम लगा नजर आया। जो स्थानीय लोगों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। हिमालय की शक्तियों को जानने की उनकी तीव्र उत्कंठा मुखरित हो रही थी। कभी देवप्रयाग के संगम में श्रद्धानत होकर डुबकी लगाते, कभी ऋषिकेश तो कभी हरिद्वार के गंगा तटों पर सूर्य साधना करते नजर आते। दरअसल 'अवेकन-द जर्नी ऑफ सेल्फ-डिस्कवरी' मुहिम में भाग लेने दुनिया के तीस देशों के करीब डेढ़ सौ साधक उत्तराखंड आए हुए थे। इन योग साधकों में ब्रिटेन, इटली, साइप्रस,अमेरिका, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, चीन, मलेशिया, यूएई, वियतनाम, मॉरीशस, त्रिनिदाद और एशिया व यूरोप के कई देशों की योगनियां शामिल थीं। पेशेवर हिसाब से देखें तो इन साधकों की विविधता समृद्ध थी। इनमे, डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद , हीलर्स, आध्यात्मिक अभ्यासकर्ता, उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान रखने वाले साधक शामिल थे। वे सभी एक ही उद्देश्य से जुटे थे, हिमालयीय आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू होना।

गंगा के विस्तृत तटों पर विदेशी साधकों का सूर्य को अर्घ्य देने अनवरत अभ्यास हर किसी को चौंकाता है। वे विभिन्न धर्मों, देशों व संस्कृति के लोग सूर्य आराधना के मंत्र उच्चारित करते नजर आते तो स्थानीय लोग हैरत में होते। उस दिन सिंगथाली गांव के ठीक नीचे पुण्य सलिला गंगा की लहरों का अंतर्मन को भिगोने वाला संगीत साधकों को सम्मोहित कर रहा था। जैसे ही सूर्य की रश्मियां टिहरी गढ़वाल की इस तलहटी में नवजीवन का संचार करने लगीं, ये तमाम विदेशी योगी-योगनियां अपने तांबे, चांदी व मिश्रित धातुओं के पात्रों से सूर्य को अर्घ्य देने लगते हैं। ये क्रम निरंतर कई घंटों तक चलता रहा। दरअसल, ये विभिन्न देशों, संस्कृतियों व धर्मों के साधक जल साधना के जरिये ध्यान की एकाग्रता का लक्ष्य हासिल कर रहे थे। पूंजीवादी के चरम वाले अमेरिका, साम्यवादी चीन, लोकतांत्रिक ताइवान, कठमुल्ला संस्कृति के वाहक ईरान व साइप्रस के विभिन्न धर्मी लोगों को सूर्य को अर्घ्य देते और सूर्य आराधना मंत्र का उच्चारण करते देखना रोमांचित करता है। ये वैश्विक पटल पर योग की जोड़ने की भारतीय संस्कृति का जीवंत उदाहरण ही है।

दरअसल, सिंगथाली के सुरम्य प्राकृतिक अधिवास में गंगा का सानिध्य इन विदेशी योग साधकों को भावविभोर

कर गया। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुषमा उन्हें मंत्रमुग्ध करती है। इस योग पर्व में उन्होंने योग के विभिन्न आयामों से रूबरू होने का शुभ अवसर पाया और इसका भरपूर लाभ भी उठाया। प्रातः कालीन सत्र में आसन, प्राणायाम व ध्यान, दिन में योग जिज्ञासाओं पर मंथन और रात्रि के सत्रों में योग के बौद्धिक विमर्श में इन विदेशी मेहमानों ने सक्रिय भागीदारी निभायी। इन विदेशी साधकों की योग जिज्ञासाओं के निराकरण के लिये कई विशेष सत्र भी इस दौरान आयोजित किए गए। वहीं गंगा के तट पर रोज होने वाला सांध्यकालीन गंगा आरती का आयोजन इन साधकों के लिये एक पर्व जैसा होता था। घाटी की गहराई में पहाड़ी इलाका होने के कारण सूर्य जल्दी ही ओझल हो जाता है। ऐसे में आरती में प्रयुक्त होने वाली कई ज्योति वाली दीप माला इन विदेशी मेहमानों के अंतर्मन को भिगो जाती थी। इसके बाद वे फिर अपनी योग साधनाओं में गहरे उतर जाते।

निस्संदेह, यह योग की ताकत ही है दुनिया की अलग-अलग शासन व्यवस्थाओं, विभिन्न महाद्वीपों, संस्कृतियों व धर्मों से जुड़े लोग यहां श्रद्धा भाव से योगिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। उनके लिये योग व ध्यान की समृद्ध परंपराएं धार्मिक विश्वासों में बाधक नहीं हैं। इसे तो योग की वैश्विक सर्वस्वीकार्यता ही कहा जाएगा कि इन युवा योग साधकों को योग की जननी भारत की धरती सम्मोहित करती है। वहीं दूसरी ओर विदेशी साधकों की उपस्थिति से ये योग उत्सव एक अद्भुत सांस्कृतिक मेला नजर आता है। इस विशिष्ट योग उत्सव में भाग लेने वालों में विदेशी कॉरपोरेट जगत के बड़े अधिकारी शामिल रहे, जो समृद्ध हासिल करने के बाद अपने भीतर की समृद्धि की तलाश में हिमालय के आंचल में आए हैं। उनमें नवविवाहित युगल, भरे-पूरे परिवार, प्रेमी युगल, विवाह को तिलांजलि देकर आई आत्मनिर्भर युवतियां और कुछ उम्रदराज महिलाएं भी शामिल रहीं।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा योग को मान्यता देने से इसकी स्वीकार्यता वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। लोग लगातार अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। निश्चित रूप से वे भारतीय योगदर्शन व योग परंपराओं को प्रमाणिक मानते हैं। विदेशी साधक मौजूदा दौर में आधुनिक चिकित्सा के साइड इफेक्ट को देखते हुए योग व प्राकृतिक चिकित्सा में रुचि ले रहे हैं। वे हिमालय की जड़ी-बूटियों को आजमा रहे हैं। निस्संदेह, इससे भारत को योग की जन्मस्थली के रूप में स्वीकार्यता मिल रही है। साधक आसन, प्राणायाम व ध्यान के साथ योगदर्शन के आध्यात्मिक पक्ष से भी अवगत हो रहे हैं। सही मायनों में योग के अभ्यास हमारे मनोकायिक रोगों के उपचार में अचूक दवा का काम करते है।

दरअसल,रोग हमारे मन की उलझनों से उपजे दोषों से भी पनपते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दिल व दिमाग को प्रदूषण से मुक्त करने के लिये योग साधना से सुकून हासिल करना उनकी प्राथमिकता है। वे हिमालय की शक्तियों व गंगा के महात्म्य को स्वीकार करते हुए वे आसपास के गंगा से जुड़े तीर्थों तक पहुंचते हैं। उन्हें देवप्रयाग का तीर्थाटन मंत्रमुग्ध कर गया। एक पूरे दिन वे अलकनंदा, भागीरथी व सरस्वती के संगम पर जल साधना के जरिये आध्यात्मिक साधना के अविस्मरणीय अनुभव हासिल करते हैं। विश्वास किया जाना चाहिए कि भविष्य में भारत से सात्विक अहसास लिये ये साधक कालांतर अपने-अपने देशों में भारत के सांस्कृतिक दूत की भूमिका निर्वहन करेंगे। भारत की समृद्ध संस्कृति का अन्य देशों में प्रसार होगा।

मानव अधिकार दिवस

हमारी दैनिक आवश्यकताएं एवं मानवाधिकार के प्रश्न

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

विश्व में प्रतिस्पर्धा है। दुनिया के सभी देश एक दूसरे से अधिक विकास करके आगे निकल जाना चाहते हैं। इन देशों में गलाकाट प्रतिस्पर्धा है। इन देशों में पर्यावरण को लेकर चिंताएं कम हैं। मनुष्य की गरिमा को लेकर कम हैं। इस ग्रह को लेकर केवल बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। आधुनिकता ने सम्पूर्ण विश्व को एक अलग ही स्तर पर प्रभावित किया है। इससे हमारी आज की पीढ़ी बहुत ही सशंकित है कि आने वाले समय में हम किस प्रकार की सभ्यता और संस्कृति के हिस्सा बनेंगे? यह चिंता जायज है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों के लिए जो थीम चुना है वह है मानवाधिकार, हमारी दैनिक आवश्यकताएं। इस थीम के मुताबिक पूरी दुनिया इस बहस में है कि क्या मनुष्य अपरिग्रह और अस्तेय के मूल्यों को समझ सका है या नहीं। इस बहस में है कि हमारी दैनिक दैनंदिन में वे कौन से तत्व हैं जो हमारी गरिमा के हनन में ज्यादा सक्रिय हैं।

विश्व मानव अधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष के विमर्श के केंद्र में है हमारी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी। इस वर्ष के केंद्र में है हमारा वातावरण। इस वर्ष के केंद्र में है हमारे मूलभूत अधिकार और हमारी आवश्यकताएं। लेकिन उन देशों का क्या जहाँ युद्ध हो रहे हैं। उन देशों का क्या जहाँ की महिलाएं शिक्षा से वंचित हैं। उनका क्या जो लोग अनागरिक होकर अपना जीवन जी रहे हैं। सबसे बुरा है अनागरिक होना। उनके मानव अधिकार की चिंता आखिर कौन करेगा। 4.4 मिलियन स्टेटलेसनेस पीपुल्स के बारे में आज कोई सोचने को तैयार नहीं है। शरणार्थी लोगों के जीवन के बारे में भी अगर विश्व के लोग बात करें तो शायद हम सम्पूर्ण रूप से मानव अधिकार के ऊपर परिचर्चा में सम्मिलित होंगे। कुछ लोगों को छोड़कर कुछ लोगों पर बात करके हम पृथ्वी के सभी नागरिकों के हितों पर बात करने से बच रहे हैं। यह बहस फिर हमारी दैनिक आवश्यकताओं की अधूरी है।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायोग को विश्वव्यापी थीम बनाने में तो आसानी है लेकिन यदि सबको बहस में उच्चायोग सम्मिलित नहीं कर पाता तो यह तो सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन यह एक बड़ा सच है कि अभी भी दुनिया में कोई ऐसा तंत्र विकसित नहीं हो सका है जो सम्पूर्ण पृथ्वी को एक बहस के साथ जोड़ सके। इससे एक सवाल मन में आना स्वाभाविक है कि क्या यह कुछेक लोगों की बहसें हैं जिस पर पूरी पृथ्वी के प्रश्नों को किनारे करके संतोष कर लिया जाता है? आखिर इन बहसों से फिर निकलना क्या है? लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ तो बातें हो रही हैं वरना दुनिया के बहुत से सवाल प्रश्नांकित भी न हों सकें और जो वैश्विक स्तर पर बहस चल रही है वह भी बंद हो जाए।

इस बार का सवाल है कि हमारा दैनंदिन क्या है और हमारे दैनंदिन की आवश्यकताएं कितना ज़रूरी हैं हमारे जीवन के लिए। इस बार का सवाल है कि दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी अपनी दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूर्ण कर पा रही है और कितने लोग वंचना के शिकार हैं। यदि हम अफगानिस्तान की स्त्रियों से पूछें तो उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं है। भारत के आसपास जेन-जी के आन्दोलनों ने कई सवालों को इस बीच उठाया है।

भारत में ही जो आबादी वंचना की शिकार है उनके जीवन की ज़रूरतें भी बहुत अहम् हैं और यदि उनके जीवन की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है तो निःसंदेह यह मानवाधिकारों का बहुत बड़ा हनन है। यह उन आबादी की गरिमा से जुड़ा प्रश्न है। भारत समेत दुनिया के बहुत से देशों में डिजटलीकरण बड़े पैमाने पर हुआ है लेकिन सबके जीवन में उतनी मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं जिससे वे डिजटलीकरण का लाभ ले सकें। यह जो अंतर है उसकी भरपाई के लिए राज्य जब तक तैयार नहीं हैं तो एक अच्छी खासी आब्दी मानव अधिकारों से वंचित रहेगी।

अब विभिन्न देशों में मानव अधिकारों को केवल मनुष्य तक नहीं देखा जा रहा है। पशुधन, पर्यावरण और जंगल भी मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, यह एक बड़ा सच है। लेकिन ऐसे बहुत से देश है जहाँ जानवर सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ जंगल सुरक्षित नहीं हैं। भारत के उत्तरी हिस्से में एक बार फिर सफ़ेद धुंध छाई हुई है। दिल्ली और आसपास के इलाक़ों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए सर्दियाँ अब मास्क पहनने, गले में जलन महसूस करने और आँखों में चुभन का मौसम बन गई है। साँस लेने की सामान्य प्रक्रिया भी, अब लोगों की सेहत के लिए नुक़सानदेह होती जा रही है। पर्यावरण पर तो कॉप-30 में कितनी बहसें अभी विगत समय में हुई हैं, पूरी पृथ्वी की इंटेलक्चुअल कम्युनिटी जानती है। ब्राज़ील के बेलेम शहर में यूएन का वार्षिक जलवायु सम्मेलन कॉप30 में स्वच्छ, स्वस्थ पर्यावरण की खूब चर्चा हुई। जलवायु अधिकार व जलवायु न्याय के लिए बातें हुई। क़ानूनी याचिका को कारगर बताया गया। लेकिन आने वाले कॉप-31 जब भी बहस के केंद्र में आएगा तो कोई भी ऐसा आंकड़ा सामने आने के आसार नहीं हैं जिससे पूरी पृथ्वी की आबादी राहत की सांस लेती नज़र आए और अपने देशों पर गर्व कर सके।

यह जो जीवन के साथ घटित होने वाले जोखिम हैं उसके पीछे कहीं न कहीं मनुष्य की लालच और उसके भयानक विकास के स्वप्न भी हैं। अब विकास को सतत विकास के साथ बहस में लाया जा रहा है लेकिन विश्व में ऐसी कोई योजना नहीं है कि बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस की चिंता को ख़त्म किया जाए। हम रोज खाते क्या हैं, पहनते क्या हैं? हम रोज जीते क्या हैं? हम रोज रहना कहाँ पसंद करते हैं? यह सब हमारा दैनंदिन का हिस्सा है। पिज्जा और बर्गर खाने वाली आज की आबादी भूखे लगों के पेट के बारे में नहीं सोचती। आज की आबादी शहरी भूख और शहरी भुलावे में गाँव की स्वच्छ हवा भी नहीं चाहती। खाती भी है अपने मन की और जीती भी है अपने मन की। लेकिन पता है यह सब तय होते हैं किसी के जीवन के साथ अतिक्रमण के साथ। यह सब पूर्ण होते हैं किसी के हक को मारकर। ऐसे में हमारे मानव अधिकार सुरक्षित होंगे कैसे?

विश्व मानव अधिकार दिवस पर हमारे देश में और दुनिया में यह अब तय करने की बारी है कि हम क्या सही भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं कि हमारा आने वाला समय बिलकुल हमसे ही रूठ कर दूर जाने वाला है। यह तय करना है कि हमारी पृथ्वी, जल-जंगल-जमीन और जीवन बचे कैसे? यह तह करना है कि हम अपने ऊपर अंकुश लगा सकते हैं या नहीं? यदि यह सब तय नहीं हुआ तो हमारा जीवन हमें छोड़ देगा और असमय छोड़ देगा। आज की चुनौतियाँ हमें आगाह कर रही हैं कि अभी सही समय है जितना खोया उसे ठीक कैसे करें, इस पर विचार करें। हमारे लीविंग स्टैण्डर्ड भले ही हमें धोखे में रखें लेकिन हमारे पूर्वज जो कि नदी के किनारे जीवन जीते थे। गाँव या जंगल में रहना पसंद करते थे। साधारण जीवन से अपने यश, बल, बुद्धि, विद्या का विस्तार करके सबके हित में कार्य करते थे वे लोग हमें धोखा नहीं देंगे। इनकी सुचिता, शुद्धता और सादगी से परहेज करती आज की आबादी को उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है तभी हम आज हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे से कर सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को सुखमय भविष्य दे पाएंगे नहीं तो एक-दूसरे का अतिक्रमण करती पीढ़िया एक दिन स्वतः अपनी करनी से समाप्त हो जाएँगी।

नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर को, संपत्ति और जलकर के प्रकरण रखेगी नगरपालिका

बकाया राशि की वसूली के लिए अधिभार छोड़ेगी नपा

एस. द्विवेदी, बैतूल। साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को किया जाएगा। इसमें बकाया संपत्ति, जल कर सहित अन्य करों की वसूली के लिए नगरपालिका अधिभार में छूट देगी। अभी शहरवासियों पर कुल 8 करोड़ 72 लाख 87 हजार 378.93 रुपये बकाया है। बताया जा रहा है कि लोक अदालत के माध्यम से बकाया राशि की वसूली को लेकर नगरपालिका अधिकारियों ने तैयारी कर ली है। नगरपालिका ने संपत्ति, जलकर सहित अन्य करों की वसूली के लिए बकायेदारों को नोटिस जारी कर दिये है। साथ ही एकमुश्त बकाया जमा करने पर अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए बकायेदारों को प्रेरित भी किया जा रहा है। हालांकि लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा बकाया वसूली हो, इसके लिए नगरपालिका पूरा-पूरा प्रयास कर रही है। बता दे कि एसआईआर में नगरपालिका के सहायक राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी लगी होने के कारण नवंबर में राजस्व वसूली की रफ्तार काफी धीमी रही या एक तरह से टैक्स वसूली पूरी तरह ठप हो गई थी। अब नगरपालिका लोक अदालत के माध्यम से बकाया टैक्स राशि की वसूली करने के लिए प्रयासरत है।

17 सहायक राजस्व निरीक्षकों की लगी थी ड्यूटी- बताया जा रहा है कि एसआईआर सर्वे में नगरपालिका के करीब 17 सहायक राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी लगी थी। जिसकी वजह से नवंबर माह में वसूली की रफ्तार धीमी रही। वैसे सहायक राजस्व निरीक्षकों द्वारा रोजाना टैक्स वसूली कर नपा के खजाने को भरने का

काम किया जाता था, लेकिन एसआईआर सर्वे के कारण वसूली को रफ्तार नहीं मिल पाई। सिर्फ काउंटर पर ही राशि जमा हो रही थी। किन्तु इस बार नगरपालिका ने बकाया संपत्ति और जलकर जमा करवाने के लिए लोक अदालत का सहारा लिया है।

बकाया राशि पर अधिभार में मिलेगी छूट- लोक अदालत के माध्यम से एकमुश्त राशि जमा करने पर बकायेदारों को अधिभार में छूट मिलेगी। नगरपालिका के राजस्व शाखा से मिली जानकारी के अनुसार शहर वासियों पर संपत्ति कर का 2,66,54,434 रूपये और जलकर का 3,00,18,142.93 रुपये बकाया है। इस बकाया राशि के लिए नगरपालिका लोक अदालत में प्रकरण रखेगी। जिसमें बकाया राशि जमा करने पर बकायेदारों को लगने वाले अधिभार में छूट मिलेगी। अनुमान है कि लोक अदालत के माध्यम से नगरपालिका अधिक से अधिक बकायादारों से टैक्स वसूली करेगी। जिससे नगरपालिका के खाली खजाने को भरने में काफी राहत मिलेगी।

सितंबर में लोक अदालत के माध्यम से वसूले थे करीब 58 लाख- नगरपालिका ने सितंबर में आयोजित हुई लोक अदालत में करीब 58 से 60 लाख रुपये वसूल किए थे। जिसमें संपत्ति और जलकर की राशि शामिल थी, वहीं नगरपालिका ने अब 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण रखकर वसूली की तैयारी की है। बताया जा रहा है कि नगरपालिका ने बकायेदारों के कम से कम 400 प्रकरण रखेगी। जिनसे बकाया राशि वसूल की जानी है। इससे नगरपालिका के राजस्व में वृद्धि होगी और लोगों को भी अधिभार में छूट का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए नगरपालिका ने लोक अदालत को लेकर नोटिस जारी कर दिये है।

कर्मियों के वेतन में देरी, नहीं हो पा रहे विकास कार्य

नगरपालिका की अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार से मिलने वाले टैक्स और शासन से मिलने वाले चुंगी कर सहित अन्य अनुदान के अलावा लोगों से वसूले जाने वाले विभिन्न करों पर निर्भर है। इससे नगरपालिका पेयजल व प्रकाश व्यवस्था, निर्माण कार्य, सफाई, वेतन आदि पर खर्च करता है। अभी नगरपालिका रोड निर्माण सहित अन्य कार्य करवा रहा है। करों की वसूली ठीक न होने से निर्माण कार्यों की गति भी धीमी हो गई थी। वहीं नपा का खजाना खाली होने से कर्मचारियों को भी वेतन दिये जाने में देरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

इनका कहना है -

लोक अदालत में संपत्ति और जलकर वसूली के लिए एकमुश्त राशि जमा करने पर अधिभार में छूट दी जाएगी। एसआईआर के काम के बाद सहायक राजस्व निरीक्षकों द्वारा नोटिस बांटे जा रहे हैं। लोक अदालत में शत-प्रतिशत बकाया वसूली का लक्ष्य है।

- सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

अग्रवाल युवक-युवती परिचय सम्मेलन के लि ए महिला कार्यकारणी गठित

धार। मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा धार द्वारा अग्रवाल समाज धार के सानिध्य में दो दिवसीय अखिल भारतीय विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन धार स्थित श्रद्धा शगुन गार्डन में 10 एव 11 जनवरी को आयोजित होगा। जिसको लेकर महिला कार्यसमिति की घोषणा की गई जिसमें संरक्षक उमा कैलाश अग्रवाल,शोभा बंशीधर अग्रवाल, मीना विट्ठलदास अग्रवाल,अनिता ओमप्रकाश अग्रवाल, वर्षा दिनेशचन्द्र अग्रवाल, कुसुम ब्रजेश अग्रवाल, मंगला डॉ. उमेश मित्तल,शीला ओमप्रकाश अग्रवाल,रुकमणी जुगलकिशौर अग्रवाल,कला महेश अग्रवाल,पद्मा सतीशचन्द्र अग्रवाल, कुसुम मनोहरलाल अग्रवाल, शीला कैलाश अग्रवाल,अध्यक्ष रेणु वल्लभदास अग्रवाल,कार्यकारी अध्यक्ष अर्चना सुनील गर्ग,महामंत्री कविता गोपीकिशन अग्रवाल,पायल आशीष गोयल,संगीता प्रहलाद अग्रवाल,लता अजय अग्रवाल,सविता डॉ. के. सी. जिन्दल,उपाध्यक्ष अंजु मुरली अग्रवाल, ममता पराग अग्रवाल, रीना दीपक अग्रवाल, सीमा द्वारका अग्रवाल, पुजा जितेन्द्र अग्रवाल, आशा अनूप अग्रवाल, माधुरी सतीश गोयल, रचना संजय अग्रवाल, सोनल सतीश अग्रवाल, मीना मोहन अग्रवाल, कविता अशोक अग्रवाल, रेखा दिपक अग्रवाल,मंत्री अमिता निमिष गोयल, बरखा सुशील गर्ग, बबिता मुकेश गोयल, मीना सुनील मित्तल, मोना लोकेश अग्रवाल, शोभा दिलीप सांघी, भावना अनिल गुप्ता, मोना प्रविण गर्ग, शिल्पा नवीन गर्ग, पिंकी पवन अग्रवाल, श्रृद्धा शेलेन्द्र अग्रवाल, रेखा राजेश मित्तल, मधु मनीष अग्रवाल, मोनिका मुकेश गोयल, निलम अर्पित अग्रवाल, दीप्ती विकास अग्रवाल, प्रीति दीपक अग्रवाल, रोशनी राकेश गर्ग, ईशा साकेत अग्रवाल,सहमंत्री अनिता आनंद अग्रवाल, भारती मनीष अग्रवाल, चन्दा शैलेन्द्र अग्रवाल, नूपुर प्रतिक मोदी, हंसा लोकेश अग्रवाल, सरोज द्वारका अग्रवाल, कामना प्रसाद अग्रवाल, अंजु राजेश अग्रवाल, सिमरन हार्दिक मित्तल, पुजा रितेश अग्रवाल, रेखा संजय अग्रवाल, श्वेता वैभव अग्रवाल, नमिता अमित अग्रवाल, निशा गोपाल अग्रवाल, निशा मनीष गुप्ता, प्रगति आशीष अग्रवाल, वर्षा विमल गर्ग, स्मिता सुधीर अग्रवाल,कोषाध्यक्ष नीलम महेश अग्रवाल,सहकोषाध्यक्ष वर्षा राजेन्द्र अग्रवाल एवं कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनित किया गया।

जानकारी मीडिया प्रभारी अशोक मित्तल एवं श्याम मंगल लेबड ने दी।

मलतास विवि में 12 व 13 दिसम्बर को नेशनल कॉन्फ्रेंस NCM-SAP 2025 का आयोजन

देवास डिपार्टमेंट ऑफ एलाइड एंड रीहैबिलिटेशन साइंसेज़, अमलतास यूनिवर्सिटी, देवास द्वारा NCMSAP 2025 - सेकंड मिड टर्म नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोसायटी फॉर एडिक्शन साइकोलॉजी का आयोजन12 व 13 दिसम्बर को किया जा रहा है। जिसमें देश-विदेश के विशेषज्ञ भाग लेंगे।

इस राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय 'एडिक्शन के कॉग्निटिव, क्लीनिकल एवं साइको-न्यूरोलॉजिकल पहलू' रखा गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य नशे और व्यसन (Addiction) से संबंधित समस्याओं को समझने और समाधान खोजने के लिए सहयोगात्मक तथा बहु-विषयक (Multidisciplinary) दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। सम्मेलन में युवाओं में बढ़ रही लत की समस्या को केंद्रित करते हुए, विभिन्न प्रकार के एडिक्शन पर चर्चा की जाएगी। आज युवाओं में नशे की समस्या पारंपरिक मादक पदार्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि गेमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन जुआ जैसे व्यवहारिक एडिक्शन भी गंभीर चुनौतियाँ बन चुके हैं। यह स्थिति न केवल युवाओं को बल्कि परिवारों, समाज और समुदायों को प्रभावित कर रही है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के विशेषज्ञ, शोधकर्ता, नीति-निर्माता, शिक्षाविद, और युवा जागरूकता से जुड़े संगठन भाग लेंगे। कार्यक्रम में एडिक्शन के कारण, इसके परिणाम और इसके समाधान के लिए नवीन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। NCMSAP 2025 देश का ऐसा प्रमुख मंच है जो पहली बार साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, नर्सिंग, रीहैबिलिटेशन, सोशल वर्क और मेडिकल साइंसेज़ को एक ही छत के नीचे जोड़कर एडिक्शन जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर एक संयुक्त पहल कर रहा है।

अमलतास विश्वविद्यालय के चेयरमैन श्री मयंक राज सिंह

सरकारी मेडिकल कॉलेज न मिला तो भिण्ड और कटनी में बंद होगा: रघु ठाकुर

भोपाल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं संरक्षक रघु ठाकुर ने कहा है कि और भिण्ड में सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला तो लोसपा दोनों शहरों में बंद आयोजित कराने का अभियान चलायेगी। रघु ठाकुर भोपाल के जहांगीराबाद स्थित नीलम पार्क में आयोजित लोसपा के धरना प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। मध्यप्रदेश के अलग अलग जिलों व शहरों से पार्टी कार्यकर्ता अपनी मांगों का ज्ञापन सरकार को सौंपने के लिए भोपाल पहुंचे थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट शम्भूदयाल बघेल सहित विभिन्न पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में रघु ठाकुर ने कहा पर्चियों से जिस तरह मुख्यमंत्री बन रहे हैं उससे लोकतंत्र में सामंतवाद की वापसी हो रही है। किसान मजदूरों की पार्टी की जगह अब जाति की पार्टियां बन रही हैं।

कटनी और भिण्ड में मेडिकल कॉलेज के लिए लोसपा के लम्बे आंदोलन के बाद सरकार ने यहां पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की तो है लेकिन लोसपा ने तय किया है कि या तो यहां पूरी तरह

से सरकारी मेडिकल कॉलेज बने, नहीं तो उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, रीवा आदि के सरकारी मेडिकल कॉलेज को भी पीपीपी मॉडल पर चलाया जाए।

लोसपा ने जिन मुद्दों को लेकर आज भोपाल में धरना प्रदर्शन आयोजित किया था उनमें कटनी व भिण्ड में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने,सरकारी संपत्तियों को बेचने और निजी क्षेत्र के कब्जे पर रोक लगाने, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को गिरफ्तार करने , अतिथि विद्वानों को नियमित करने, किसानों को खाद- बीज पर्याप्त मात्रा में समय पर मुहैया कराने व वर्षा से फसल खराब होने पर बीस हजार रुपए प्रति एकड़ हर्जाना देने की मांग विशेष रूप से शामिल है। अंचल से आये लोगों ने धरने में गोचर भूमि पर अवैध कब्जे और किसानों को मनमाने बिजली बिल थमाए जाने और खाद की भारी किल्लत का मुद्दा भी उठाया।

रघु ठाकुर ने कहा लोसपा की नीति है कि एक घर में एक कार होनी चाहिए और नये कारखाने पुराने बंद कारखानों की जमीन पर लगना चाहिए नहीं तो जमीन निजी उद्योगों को कौड़ियों के मोल देने के बजाय मूल किसानों को वापस किया जाना चाहिए, रोजगार भी वहां के लोगों को मिले जहां की जमीन कारखाने को गयी है।

अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर बोलते हुए श्री ठाकुर ने कहा जहां सरकारी सड़क है उसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो।

संसद व विधानसभाओं के लगातार छोटे होते सत्र और दलों में खत्म होते आंतरिक लोकतंत्र पर चिंता जताते हुए रघु ठाकुर ने कहा सच्चे लोकतंत्र की वापसी के लिए सरकारों को समय समय पर बदलना और सही विकल्प का चुनाव करना जरूरी हो गया है।

कैलाशचंद्र जैन के निधन पर परिवारजनों ने नेत्रदान किए, धार का 26वां नेत्रदान

धार। शहर की लाडगली निवासी श्री कैलाशचंद्र जैन की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र सचिन जैन और उनकी धर्मपत्नी ने उनके नेत्रदान करने की इच्छा धार मानव सेवा कल्याण समिति के समक्ष जताई। समिति ने भोज हॉस्पिटल के नेत्र विभाग की कर्मा मुजाल्दा और उनके सहायक पीयूष परमार के सहयोग से नेत्रदान की प्रक्रिया संपन्न कराई। जो धार नगर का मानव सेवा कल्याण समिति द्वारा किया गया 26 वां नेत्रदान है। यह नगर मे दूसरा अवसर है जब एक दिन में दो दो नेत्रदान हुए है। ये धार नगर की जनता का नेत्रदान, अंगदान और देहदान के प्रति बढ़ती जागरुकता का प्रमाण है। समिति ने परिवार का नेत्रदान करने हेतु आभार व्यक्त किया।

विधायक श्री खंडेलवाल ने प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने किसानों को किया प्रेरित

बैतूल। दो दिवसीय जिला स्तरीय प्राकृतिक कृषि मेले का आयोजन सोमवार से पुलिस ग्राउंड बैतूल में किया जा रहा है। मेले के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष व बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने किसानों को प्राकृतिक कृषि, जैविक खेती की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। विधायक श्री खंडेलवाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत में भारी कमी आती है, मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है और फसलों की सेहत बेहतर होती है। इसके अलावा उन्होंने किसानों को कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से सत्तक संपर्क में रहने की अपील करते हुए वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई तकनीकों का कृषि में उपयोग करने का आह्वान किया। आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने कहा कि मानव स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक उत्पाद एवं स्थानीय स्तर के उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की सलाह दी। मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि से उत्पादित अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।

महिला किसानों ने जीवामृत तैयार करने का किया जीवंत प्रदर्शन- उप संचालक कृषि डॉ. आनंद कुमार बडोनिया ने बताया कि मेले में किसानों को उन्नत तकनीक एवं प्राकृतिक कृषि का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। जिला स्तरीय प्राकृतिक मेला में महिला किसानों ने जीवामृत तैयार करने का जीवंत प्रदर्शन किया गया, जिसे सभी अतिथियों एवं किसानों के द्वारा देखा गया। इसके अलावा अतिथियों के द्वारा सभी स्टाल का अवलोकन कर किसानों के उत्पाद को सराहा गया। वहीं मेले में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा स्थानीय जलवायु अनुरूप कृषि कार्यमाला अपनाने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस दौरान सभी सहयोगी विभाग जैसे उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्यपालन, रेशमपालन आदि विभागों के द्वारा विभाग की प्रमुख योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। मेले में प्रगति ग्रामीण विकास संस्था बैतूल, कृषि एजेंसी बैतूल गंज, श्री जयराम गायकवाड डेरी एवं ऑर्गेनिक कृषि फार्म ग्राम बघौली बैतूल, घोघीर एग्रोफेड फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमि. बैतूल, प्रगति आजीविका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमि.मुलताई, प्रत्याशा फाउंडेशन बैतूल, सतपुडांचल किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड शाहपुर, श्रीजी शुगर मिल, प्रदान संस्था के द्वारा उत्पादित अनाज एवं विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन स्टॉल लगाए गए। इसके अलावा मछली पालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग, जिला व्यारपार एवं उद्योग केन्द्र , एम.पी.एग्रो इंड.डे. कार्पो., जल संसाधन विभाग, कृषि अभियांत्रीकी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा योजनाओं के स्टाल लगाकर किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार, भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष महेश्वर सिंह चंदेल, माधोराव नानकर, सभापति कृषि स्थाई समिति जनपद पंचायत बैतूल इन्द्रपाल पुन्डे, भोला खंडेलवाल, प्रमोद राठौर, ममता मालवीय, दीपक कपूर आदि उपस्थित रहे।

सांसद खेल महोत्सव के तहत दौड़, कूद एवं रस्साकसी प्रतियोगिता सम्पन्न

ब्लॉक समन्वयक सुश्री सलमा खान ने बताया कि रस्साकसी में 7 टीम बालक बालिका वर्ग में शामिल हुई एवं एथेलेटिक्स में 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया

हरदा (निप्र)। सांसद खेल महोत्सव के तहत हरदा खिरकिया विधानसभा स्तरीय प्रतियोगिता अंतर्गत रविवार को नेहरू स्टेडियम हरदा में एथेलेटिक्स एवं रस्साकसी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ ब्लॉक समन्वयक सुश्री सलमा खान, क्रीड़ा अधिकारी रामनिवास जाट, जिला खेल प्रशिक्षक सुश्री मोनिका मेहता, ब्लॉक समन्वयक श्री संदीप जाट, एथेलेटिक्स कोच श्री रोनित राठौर ने मैदान की पूजन कर किया। ब्लॉक समन्वयक सुश्री सलमा खान ने बताया कि रस्साकसी में 7 टीम बालक बालिका वर्ग में शामिल हुई एवं एथेलेटिक्स में 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। रस्साकसी बालिका वर्ग में प्रथम स्थान बालिका छात्रावास हरदा, दूसरा स्थान शास उत्कृष्ट विद्यालय हरदा तथा तीसरा स्थान कन्या शाला हरदा की बालिकाओं ने प्राप्त किया। बालक वर्ग में प्रथम स्थान ग्राम नीमगांव, दूसरा स्थान शास डिग्री कॉलेज हरदा व तीसरा स्थान बालक उत्कृष्ट छात्रावास हरदा ने प्राप्त किया। एथेलेटिक्स बालक वर्ग 100 मीटर में प्रथम स्थान फाजिल खान, दूसरा स्थान पवित्र परासर व तीसरा स्थान रोशन वैष्णव ने प्राप्त किया। इसी प्रकार 200 मीटर में प्रथम स्थान तन्मय झिंझोरे, दूसरा स्थान वसंत माणिक व तीसरा स्थान हर्षवर्धन शुक्ला तथा 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान मेहरबान चौहान, दूसरा स्थान फाजिल खान व तीसरा स्थान विनायक ने प्राप्त किया। इसी तरह 800 मीटर दौड में प्रथम स्थान दीपक राजपूत, दूसरा स्थान तन्मय झिंझोरे व तीसरा स्थान गोविंद भार्गव तथा 1500 मीटर में प्रथम स्थान पंकज उइके, दूसरा स्थान दीपक राजपूत व तीसरा स्थान गोविंद भार्गव ने प्राप्त किया। सुश्री खान ने बताया कि लंबीकूद में प्रथम स्थान मनीष कासदे, दूसरा पवित्र पारासर व तीसरा स्थान अभिषेक चाकरदे, गोला फेंक में प्रथम स्थान रोनित राठौर, दूसरा स्थान धर्मेंद्र बचनिया व तीसरा स्थान बालकृष्ण, भाला फेंक में प्रथम स्थान नितेश, दूसरा स्थान मनीष कासदे व तीसरा स्थान बालकृष्ण मक़ाम ने प्राप्त किया। बालिका वर्ग 100 मीटर में प्रथम स्थान आयुषी राठौर, दूसरा स्थान रजनी कलम व तीसरा स्थान रिद्धि चौधरी, 200 मीटर में प्रथम स्थान कल्पना कलम, दूसरा स्थान रजनी कलमें व तीसरा स्थान कनक मालवीय, 400 मीटर में प्रथम स्थान गौरी यादव, दूसरा स्थान रजनी कलमें व तीसरा स्थान कल्पना कलम, 800 मीटर में प्रथम स्थान आयुषी जात्रे, दूसरा स्थान रजनी कलम व तीसरा स्थान रघुमा खातून तथा 1500 मीटर में प्रथम स्थान अंजली चावल, दूसरा स्थान रघुमा खातून व तीसरा स्थान पूजा उइके ने प्राप्त किया।

इसी प्रकार लंबीकुद में प्रथम स्थान कनक सोलंकी, दूसरा स्थान रजनी कलमें व तीसरा स्थान रिया कलम, गोला फेंक में प्रथम स्थान कनक सोलंकी, दूसरा स्थान रजनी कलमें व तीसरा स्थान दीक्षा श्रीवास ने प्राप्त किया। सांसद खेल महोत्सव के तहत शनिवार को हरदा खिरकिया विधानसभा स्तरीय कब्बड्डी एवं पिट्ठू प्रतियोगिता आयोजित की गई। कबड्डी में हरदा एवं खिरकिया क्षेत्र से हंडिया, नयापूरा, खेड़ा, सोनतालाई, मांदला, खिरकिया, मसनगांव, शास महात्मा गांधी, शास उत्कृष्ट विद्यालय हरदा, शास नगरपालिका स्कूल हरदा, शासकीय कन्या शाला, सनफ्लॉवर स्कूल हरदा, इंपीरियल पब्लिक स्कूल खिरकिया, चारूवा, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा, हरदा वांडर्स हरदा, कुंजरगांव, कायागांव, मां राजरानी क्लब हरदा, छीपाबड़, मगरधा, बालगांव की 29 टीम एवं पिट्ठू की 7 टीम के लगभग 450 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला अध्यक्ष भाजपा श्री राजेश वर्मा, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी डॉ.एच. पी. सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी श्री डी. एस. रघुवंशी, डीपीसी श्री बलवंत पटेल, श्री गिरिजा शंकर राजपुत, श्री रामनिवास जाट, श्री बसंत राजपूत, श्री सौरभ तिवारी ने खिलाड़ियों परिचय किया। जिला अध्यक्ष भाजपा श्री वर्मा ने टॉस कर कबड्डी मैच प्रारंभ किया। ब्लॉक समन्वयक सलमा खान ने बताया कि पिट्ठू प्रतियोगिता बालक वर्ग में प्रथम स्थान पर डिग्री कालेज हरदा, द्वितीय स्थान पर खिरकिया व तीसरा स्थान ग्राम मगरधा रहा। बालिका में प्रथम स्थान हरदा आदर्श कॉलेज हरदा व दूसरा स्थान मगरधा ने प्राप्त किया। कबड्डी बालिका वर्ग में प्रथम स्थान मां राजरानी क्लब हरदा, दूसरा स्थान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय हरदा व तीसरा स्थान कन्या शाला हरदा ने प्राप्त किया। सुश्री खान ने बताया कि बालक वर्ग में 24 टीम शामिल हुई। सभी ने अपने नाक आऊट मैच खेले। प्रथम सेमीफाइनल मां राजरानी क्लब हरदा विरुद्ध मारुति फिजिकल अकादमी ए टीम तथा दूसरा सेमीफाइनल मैच ग्राम रेलबा विरुद्ध मारुति फिजिकल अकादमी बी टिम के मध्य हुआ। फाइनल मुकाबला फिजिकल अकादमी ए टीम विरुद्ध मारुति फिजिकल अकादमी बी टिम के मध्य हुआ। फिजिकल अकादमी बी टीम ने 25 अंक जबकि ए टीम ने 23 अंक अर्जित किए। इस प्रकार बी टिम विजेता तथा ए टीम उपविजेता रही।

संक्षिप्त समाचार

एक बगिया मां के नाम योजना के क्रियान्वयन में गति लाने दिए निर्देश

हरदा (निप्र)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजलि जोसेफ ने मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन के मैदानी अमले एवं कृषि सखी की बैठक आयोजित कर एक बगिया मां के नाम के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि सखियों से चर्चा के दौरान कहा कि जिले में अधिक से अधिक हितग्राहियों से संपर्क कर पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाए। उन्होंने जिला परियोजना प्रबंधक श्री रामनिवास कालेश्वर व जिला प्रबंधक श्री राधेश्याम जाट को खिरकिया विकासखण्ड में योजना के कार्यों को गति लाने हेतु निर्देश दिए। इसी क्रम में जिला परियोजन प्रबंधक श्री कालेश्वर ने शनिवार को खिरकिया विकासखण्ड में कृषि सखियों की बैठक आयोजित कर एवं मुहाल कला ग्राम का भ्रमण कर मां की बगिया के कार्यों को देखा। उन्होने टिमरनी विकासखंड में कृषि सखीयों की बैठक कर योजना के कार्यों में गति लाने हेतु कार्य योजना तैयार की।

रजक समाज का स्नेह मिलन-सत्कार समारोह आयोजित

इटारसी (निप्र)। रजक पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वावधान में रविवार को नर्मदापुरम जिला स्तरीय रजक समाज स्नेह मिलन एवं सत्कार समारोह किया गया। कार्यक्रम ईश्वर रेस्टोरेंट में हुआ। रजक पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मप्र प्रभारी राजकुमार मालवीय ने बताया कि समारोह में नपाध्यक्ष पंकज चौरे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार मालवीय, जिलाध्यक्ष अशोक मालवीय और समाजसेवी मनोज मालवीय ने सभी समाजसेवियों, कार्यकर्ताओं और उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद किया।

नर्मदा-तवा नदी किनारे खेत में मिली मानव खोपड़ी

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम के ग्राम मगरिया में नर्मदा और तवा नदी किनारे स्थित एक खेत में मानव खोपड़ी मिलने से सनसनी फैल गई। खेत मालिक सालिकराम तिवारी ने सोमवार सुबह 7 बजे सिंचाई के दौरान इसे देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची माखननगर पुलिस ने धड़ तलाशने के लिए करीब एक किमी के दायरे में सर्चिंग की, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा नहीं मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही माखननगर थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके और एसआई अशोक बरबड़े पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल अधिकारी ऋषिकेश यादव को भी मौके पर बुलाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि खोपड़ी काफी पुरानी है और कंकाल बन चुकी है, हालांकि उससे अभी भी बदबू आ रही थी।

जांच के लिए भोपाल भेजी जाएगी खोपड़ी

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि खोपड़ी पुरुष की है या महिला की। इसकी पहचान और विस्तृत जांच के लिए इसे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल भेजा जाएगा। वहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जांच से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जानवरों द्वारा खींचकर लाने की आशंका

पुलिस के मुताबिक, सालिकराम तिवारी का खेत नर्मदा और तवा नदी के किनारे है। आशंका जताई जा रही है कि किसी शव का जलदाग (नदी में विसर्जन) या दफन किया गया होगा, जिसे कुत्ते या अन्य जानवर खींचकर खेत तक ले आए होंगे। फिलहाल पुलिस सभी एंगल्स पर जांच कर रही है।

राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने आर्ष गुरुकुल नर्मदापुरम में पुस्तकालय भवन निर्माण का किया भूमिपूजन

नर्मदापुरम (निप्र)। राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया ने रविवार को आर्ष गुरुकुल नर्मदापुरम परिसर में पुस्तकालय भवन कक्ष निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। यह निर्माण कार्य राज्यसभा सांसद श्रीमती नारोलिया की सांसद निधि 10 लाख की राशि से कराया जा रहा है।भूमि पूजन स्वामी ऋतस्पति परिवाजक नैस्टिक के आचार्यत्व में धार्मिक विधि विधान से सम्पन्न हुआ। भूमिपूजन समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव, कुंवर सिंह यादव, अखिलेश खंडेलवाल,भारत सिंह राजपूत, मनोहर बडानी, राजेश तिवारी, अमित माहला, लक्ष्मण सिंह बेस, संजीव मालवीय, विकास नारोलिया, रूपेश राजपूत, विपिन यादव, दीपक महालह, विधायक प्रतिनिधि महेन्द्र यादव, पार्षद बिंदिया मांझी, पार्षद निर्मला हंसराय, प्रशांत पालीवाल, सुमित गौर, कमल चव्हाण, संतोष मीना, योगेन्द्र सोलंकी, सचिन तोमर, सुचित्रा यादव, चंचल राजपूत, वंदना महतो, मनीष परदेशी, हरि शर्मा, धर्मेंद्र जाट, अनूप रिझारिया, वैजन्ती, सौम्या राजपूत, पंकज बरगले, ऋषभ शुक्ल, गुरुकुल के स्वामी सप्तसिंधु जी, ब्रह्मचारीगण सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने आर्ष गुरुकुल परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा यह कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी है।

दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान : द्वितीय चरण खंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न

विदिशा (निप्र)। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के अंतर्गत द्वितीय चरण का खंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर ग्राम बतीसा स्थित शिव नंदी गौशाला, ग्राम पंचायत पुरवाई, विकासखंड बासौदा में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। शिविर में अभियान हेतु नामांकित सभी 35 प्रशिक्षणार्थी पूर्णतः उपस्थित रहे। प्रशिक्षण सत्र का संचालन मास्टर ट्रेनर एवं विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. एस. उपाध्याय द्वारा किया गया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को अभियान के तहत की जाने वाली समस्त गतिविधियों, तकनीकी प्रक्रियाओं एवं कार्य पद्धतियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

पशु चिकित्सा संबंधी प्रमुख कार्य

गौशाला में बिना टैग के 25 पशुओं का कान-टैगिंग कार्य पूरा किया गया।आठ अनुपयोगी बछड़ों का बधियाकरण किया गया।संरक्षित 63 प्रजनन योग्य गायों का गर्भ परीक्षण किया गया, जिनमें से 16 गायें गर्भवती पाई गईं।शेष गायों का डीवर्मिंग एवं आवश्यक उपचार किया गया।बहुउद्देश्यीय शिविर के अंतर्गत आसपास के पशुपालकों के 120 पशुओं का परीक्षण एवं उपचार किया गया।

विशेष सहयोग

गौशाला संचालक श्री हिम्मत सिंह गुर्जर की गरिमामयी उपस्थिति एवं सहयोग उल्लेखनीय रहा। शिविर को सफल बनाने में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी श्री रघुवीर सिंह, श्री अशोक कुमार शर्मा, श्री सोहनलाल, श्री संतोष कुमार शर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र रघुवंशी सहित विकासखंड के सभी गौ सेवक एवं मैत्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

क्षमता निर्माण

नव प्रशिक्षित एवं लंबे समय से निष्क्रिय रही मैत्रियों को हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया गया तथा उन्हें फील्ड कार्य के लिए सक्षम बनाया गया।

विमुक्त जाति प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास का निरीक्षण

विदिशा (निप्र)। शमशाबाद तहसीलदार श्रीमती लता पाल ने आज शमशाबाद स्थित विमुक्त जाति प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास का विस्तृत निरीक्षण किया गया। उन्होंने छात्रावास परिसर, भोजनालय, आवासीय कक्ष, स्वच्छता व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था तथा मूलभूत सुविधाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया है। तहसीलदार ने छात्रावासीय विघार्थियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन व्यवस्था, अध्ययन सामग्री, उपस्थिति, परीक्षा तैयारी एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं से स्कूल में नियमित उपस्थित रहने, समय पर अध्ययन करने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को तुरंत छात्रावास अधीक्षक को अवगत कराने हेतु प्रेरित किया। तहसीलदार श्रीमती पाल ने छात्रावास में उपलब्ध पेयजल, शौचालय व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा रजिस्टर, रसोईघर, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं उनके भंडारण की भी जाँच की। आवश्यक सुधार योग्य बिंदुओं पर संबंधित अधिकारी एवं छात्रावास प्रबंधन को उचित निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि छात्रावास में रहने वाली प्रत्येक छात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहते हुए सभी छात्राओं को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।निरीक्षण के दौरान छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

मतदान केन्द्र क्रमांक 24 एवं 25 पर मतदाताओं से चर्चा कर एसआईआर के कार्य में सर्च नहीं हुये मतदाताओं की लिस्ट का वाचन किया

नर्मदापुरम (निप्र)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में गणना पत्रक के डिसटाईजेसन के उपरांत जो मतदाता सर्च नहीं हो रहें हैं या स्थानांतरित हो गये हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में होशंगाबाद विधानसभा 137 अंतर्गत ग्राम पंचायत बुधवाडा के मतदान केन्द्रं क्रमांक 24 बुधवाडा एवं मतदान केन्द् ंक्रमांक 25 आगरा कला का निरीक्षण किया में एसआईआर के कार्य में जो नाम शेष बचे हैं एवं जो सर्च नहीं हो पा रहे हैं उन नामों की सूची का वाचन मतदान केन्द्र पर किया गया। साथ ही ग्रामीणों से नाम सर्च कराने के लिय सहयोग की अपेक्षा भी की। मतदाता सूची वाचन के दौरान बीएलओ अनीता शर्मा एवं अमिता गौर सहित ग्राम के सरपंच श्री राम दुलारे यादव, मांगीलाल यादव भूतपूर्व सरपंच, लीलाधर बरेले पंच, संतोष मेहरा ग्राम कोटवार, किरण राजेरिया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कृष्णा कुशवाहा आंगनवाडी सहायिका शिक्षक अंजू लता तिवारी, पज्ञा शर्मा, सुनील गौर, ग्राम के चंद्राबाई सविता यादव सुनील सेलुकर सहित दर्जनों मतदाता दोंनों मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहे।

केन्द्रीय जेल में मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया

नर्मदापुरम (निप्र)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल एवं जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल के आदेश के अनुपालन में प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में एक दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना है जिसमे अनुक्रम में केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम के खण्ड-अ में निरूद्ध बंदियो हेतु जिला चिकित्सालय नर्मदापुरम मन कक्ष द्वारा एक दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में जिला चिकित्सालय नर्मदापुरम मन कक्ष से सुश्री नाजिया सिद्धिकी (क्लीनिकल सॉयक्लोजिस्ट), श्रीमति निधि पटवा नर्सिंग ऑफिसर द्वारा परिरुद्ध 49 पुरुष बंदी एवं 16 महिला बंदी कुल 63 बंदियो की स्क्रीनिंग कर परामर्श दिया गया। आयोजित शिविर के दौरान श्री प्रहलाद सिंह बरकडे उप अधीक्षक श्री हितेश चंडिया अष्टकोण अधिकारी, डॉ. विपिन अहिरवार जेल चिकित्सक, श्रीमति इंदुराज साहू (मेलर्नस) एवं जेल स्टाफ उपस्थित रहे।

नर्मदापुरम में इलाज के नाम पर धर्मांतरण की आशंका

नर्मदापुरम में इलाज के नाम पर धर्मांतरण की आशंका

आर्थिक लालच देकर मत परिवर्तन के आरोप, उग्र आंदोलन की चेतावनी

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिले के ग्राम जमुनिया में रविवार को रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मकान में प्रार्थना के लिए जुटे आदिवासी ग्रामीणों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार, आदिवासी महिला-पुरुष शैतान बाधा दूर कराने और बीमारियों का इलाज करवाने के लिए यहां पहुंचे थे, जहां क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े एक व्यक्ति द्वारा विशेष प्रार्थना कराई जा रही थी।

इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और धर्मांतरण की आशंका व्यक्त करते हुए प्रार्थना पर आपत्ति दर्ज कराई। विहिप पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि आदिवासी समुदाय के लोगों को इलाज और

चमत्कार के नाम पर धर्म परिवर्तन की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। विहिप पदाधिकारियों द्वारा बनाए गए वीडियो में एक महिला झूमती हुई दिखाई दी, जबकि दूसरी महिला ने कहा कि उसके शरीर पर 'शैतान का असर' हो रहा है। गांव के कई लोग प्रार्थना कराने वाले व्यक्ति के पास बीमारी दूर करने की उम्मीद में पहुंचे थे।

विहिप ने पुलिस चौकी में शिकायत की

विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सेमरी हरचंद पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि ग्राम जमुनिया में पाश्चर भागचन्द्र राज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आर्थिक लालच और चमत्कारिक उपचार के दावा कर धर्मांतरण की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 का संभावित उल्लंघन हो सकता है। संगठनों ने निष्पक्ष जांच और वैधानिक कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सोहागपुर थाना प्रभारी ऊषा मरावी ने बताया कि विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है और पूरी घटना की जांच कराई जा रही है।

इटारसी में गजपुर रेलवे ट्रैक पर युवक का मिला शव

इटारसी (निप्र)। रविवार सुबह इटारसी के ग्राम गजपुर के पास डाउन रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला। यह घटना खंबा नंबर 760/26-28 के करीब सुबह 6:57 बजे सामने आई। प्राथमिक जांच में इसे रेल दुर्घटना का मामला माना जा रहा है। गुर्रा स्टेशन के पॉइंट्समैन दीपक कहार (40) ने रेल मार्ग की नियमित पेट्रोलिंग के दौरान ट्रैक के किनारे शव देखा। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना रामपुर गुर्रा पुलिस को दी। मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष अनुमानित है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

मुख्यमंत्री ने राजनगर में 510 करोड़ लागत के 29 विकास कार्यों का किया भूमि-पूजन और लोकार्पण

बुंदेलखंड धरा है हीरों और महावीरों की : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बुंदेलखंड हीरों और महावीरों की धरती है। यह मंदिरों की नगरी है। उन्होंने कहा कि महाराज छत्रसाल के कार्य काल में बुंदेलखंड की महाविजय होती थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाराजा छत्रसाल के शौर्य को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि बुंदेलखंड के गौरव महाराज

- **एक करोड़ 26 लाख से अधिक लाड़ली बहनों को 1857 करोड़ रुपए अंतरित**
- **बहनों के आशीर्वाद से राज्य सरकार निरंतर कर रही है विकास कार्य**

छत्रसाल की प्रतिमा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का खजुराहो में अनावरण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव छतरपुर के राजनगर में लाड़ली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को 1857 करोड़ रुपए राशि अंतरित की गई है। इनमें छतरपुर की 3 लाख 24 हजार से अधिक लाड़ली बहनें शामिल हैं। हितग्राहियों बहनों को उनके बैंक खातों में 31वीं किस्त के रूप में 1500 रुपए की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में अब तक 46 हजार 500 करोड़ की राशि बहनों के खातों में अंतरित की जा चुकी है। बहनें अपने परिवार के संचालन में भी सहयोग कर रही हैं। बहनों के आशीर्वाद से राज्य सरकार निरंतर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बहनों को पक्के मकान और उज्जवला गैस कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुंदेलखंड के चहुँमुखी विकास के लिए 270 करोड़ लागत के 9 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और 240 करोड़ लागत के 20 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें 2 सांदीपनि विद्यालय और स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खजुराहो में बड़ा कन्वेंशन सेंटर और फाइव स्टार होटल बनाया जाएगा। राजनगर में राजगढ़ पैलेस की सौगत मिल रही है। इससे पर्यटन क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। बुंदेलखंड के दमोह, छतरपुर, पन्ना और कटनी में 4 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जायेंगे। केन-बेतवा लिंक परियोजना से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 2 नेशनल हाइवे को जोड़ने वाले फोर लाइन सड़क की सौगात दमोह-सागर को मिलने जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सागर में नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाएगा। इससे 30 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजनगर में आयोजित लाड़ली बहना सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी किया।

खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुंदेलखंड के चहुंमुखी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राज्य सरकार जो कहती है करके दिखाती है। सरकार ने लाड़ली बहनों के खातों में प्रतिमाह 3000 रुपए भेजने का संकल्प लिया था, जिसे धीरे-धीरे पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राजनगर विधायक श्री अरविंद पटेरिया ने कहा कि बुंदेलखंड में 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अनुपम सौगात दी है। पिछले 2 वर्षों में खजुराहो में विकास से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। आज सूखे और पिछड़े बुंदेलखंड को विकास की नई पहचान मिल रही है।

आलू-गोभी की सब्जी बनी 'जहर'

खजुराहो के रिसॉर्ट में 3 मौत के बाद सड़क पर उतरे लोग, परिजन को आर्थिक मदद

खजुराहो (नप्र)। खाना खाने से बीमार हुए गौतम होटल खजुराहो के 3 कर्मचारियों की मौत पर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने तत्काल मृतकों के परिजन को रेडक्रॉस सोसाइटी से 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की। इसके अलावा 5-5 हजार रुपए की अंत्येष्टि सहायता राशि दी

गई। और कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित के परिजन को संबल योजना अंतर्गत 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की जा रही है। गौतम होटल खजुराहो में खाना खाने से प्रागीलाल कुशवाहा, गिरजा रजक और रामस्वरूप कुशवाहा की जान गई है।

ग्वालियर में 6 लोग भर्ती हैं

खजुराहो निवासी प्रमोद रजक ने बताया कि ग्वालियर में 6 लोग भर्ती हैं। तीन लोग गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर रखे गए हैं। दो लोगों का वार्ड में इलाज चल रहा है। एक की हालत ठीक है।

पति के पास पत्नी की बेवफाई का सबूत, कोर्ट ने तस्वीरों को माना सही

कहा-शादी के मामलों में इंडियन एविडेंस एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं होता

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि विवाहेत्तर यौन संबंध के आधार पर तलाक की डिक्री जारी करने में 65-बी सर्टिफिकेट के बिना तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिस विशाल धगट और जस्टिस बी पी शर्मा की युगलपीठ ने यह स्पष्ट किया कि शादी के मामलों में इंडियन एविडेंस एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं होता है। कोर्ट ने इस आधार पर दायर एक अपील को खारिज कर दिया।

महिला ने दी थी तलाक को चुनौती- यह मामला बालाघाट की एक महिला से जुड़ा है, जिसने कुटुंब न्यायालय द्वारा तलाक की डिक्री जारी करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। महिला का कहना था कि उसके पति ने एक अन्य व्यक्ति के साथ उसकी आपत्तिजनक तस्वीरों का इस्तेमाल करके तलाक के लिए आवेदन किया था। महिला की ओर से यह भी दलील दी गई थी कि इन तस्वीरों

के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत 65-बी सर्टिफिकेट पेश नहीं किया गया था, जो कि जरूरी है। महिला ने सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि 65-बी सर्टिफिकेट के बिना तलाक का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। उसने यह भी बताया कि तस्वीरें गलती से उसके मोबाइल से पति के मोबाइल में ट्रांसफर हो गई थीं और बाद में पति ने उसका फोन तोड़ दिया था।

शादी के मामलों में पूरी तरह लागू नहीं होता एक्ट- लेकिन, युगलपीठ ने अपने फैसले में कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट शादी के मामलों में पूरी तरह से लागू नहीं होता है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 14 के अनुसार, कुटुंब न्यायालय को सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी भी तरह की रिपोर्ट, बयान या डॉक्यूमेंट्स को सबूत के तौर पर स्वीकार करने का अधिकार है। कोर्ट ने माना कि कुटुंब न्यायालय ने इन तस्वीरों पर भरोसा करके कोई गलती नहीं की।

सीहोर के होटल में राजस्थानी कपल का प्राइवेट वीडियो बनाया

युवक ने रिकॉर्ड कर दोस्तों को भेजा, 4 पर एफआईआर ; कुबेरेश्वर धाम घूमने आए थे

सीहोर (नप्र)। सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम क्षेत्र के एक होटल में ठहरे राजस्थान के कपल का प्राइवेट वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। युवक ने चोरी-छिपे वीडियो रिकॉर्ड कर अपने दोस्तों को भेज दिया। मामले में मंडी थाना पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। कपल कुबेरेश्वर धाम दर्शन के लिए राजस्थान

से सीहोर आया हुआ था और क्षेत्र के एक होटल में ठहरा था। इसी दौरान पास के एक अन्य होटल में काम करने वाले युवक ने कमरे की लाइट जलती और पर्दा खुला होने का फायदा उठाकर कपल का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। इसके बाद उसने वीडियो अपने दोस्तों को भेज दिया, जिसके बाद वीडियो फैल गया।

होटल मैनेजर की शिकायत पर खुला मामला- होटल डमरूवाला के मैनेजर कृष्णपाल उर्फ कृष्णा वर्मा ने 8 दिसंबर को मंडी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक सुमित पैरवाल के मोबाइल में कपल का आपत्तिजनक वीडियो मिला।

शीत लहर से कंपकपाया प्रदेश रायसेन में फसल पर जमी ओस

पचमढ़ी में झील के पानी से उठ रही भाप

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में अगले 3 दिन कोल्ड वेव यानी शीतलहर का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, शाजापुर, जबलपुर, सिवनी, शहडोल में मंगलवार को कोल्ड वेव और नरसिंहपुर में कोल्ड डे का असर था। कई शहरों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है।

इससे पहले सोमवार-मंगलवार की रात में पूरा प्रदेश कांप उठा। कड़ाके की ठंड की वजह से कई शहरों में रात का पारा लुढ़क गया। मंगलवार सुबह रायसेन में फसलों पर ओस की बूंद जम गई तो पचमढ़ी में पारा 5 डिग्री पर पहुंच गया। यहां झील के पानी से भाप भी उठती नजर आई।

भोपाल में सुबह से ठंड का तेज असर रहा। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर में भी पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। भोपाल में 7.2 डिग्री, इंदौर में 6.1, ग्वालियर में 9, उज्जैन में 9.5 और जबलपुर में तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार की रात में राजगढ़ में 5.6 डिग्री, नौगांव में 6, उमरिया में 6.4, रीवा में 7.5, मलाजखंड में 7.6, बैतूल में 8.6,

शिवपुरी-मंडला में 8, दतिया-खजुराहो में 9, नरसिंहपुर-सतना में 9.2, छिंदवाड़ा में 9.6, सीधी और टीकमगढ़ में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

रीवा में ठंड और गलन बढ़ी- रीवा में पिछले एक सप्ताह से ठंड और गलन बढ़ गई है। हालांकि मंगलवार सुबह धूप जल्दी निकल आई, लेकिन गलन रही। बड़ी संख्या में लोग रीवा के अटल पार्क में ठंड से बचाव के लिए एक्सरसाइज करते नजर आए। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले एक सप्ताह में कोहरे का असर काफी बढ़ जाएगा। मंडला जिले में मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह कोहरे का असर कम था। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है।

अगले 3 दिन इन जिलों में चलेगी सर्द हवाएं- भोपाल, इंदौर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, शाजापुर, जबलपुर, सिवनी, शहडोल में कोल्ड वेव और नरसिंहपुर में कोल्ड डे का असर रहेगा। 10 और 11 दिसंबर को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, सिवनी और शहडोल में शीतलहर का अलर्ट है।

खाद तो नहीं मिली, मौत जरूर मिल गई...

3 दिन से यूरिया की लाइन में लगे किसान ने तोड़ा दम

टीकमगढ़ (नप्र)। जिले में यूरिया खाद की समस्या के चलते एक किसान की मौत हो गई। मृतक किसान जमुना कुशवाहा (50) कारी बजरुआ गांव के रहने वाले थे। वह तीन दिन से खाद के लिए लाइन में लगे थे और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि

मौत खाद की लाइन में लगने से तबीयत बिगड़ने के कारण हुई है। हालांकि, पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि मौत हार्ट अटैक से हुई है।

किसानों को हो रही परेशानी- मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में यूरिया खाद की किल्लत के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या के चलते एक किसान की जान चली गई। मृतक किसान की पहचान जमुना कुशवाहा (50) के रूप में हुई है, जो कारी बजरुआ गांव के निवासी थे। यह घटना जिले में खाद की गंभीर समस्या को उजागर करती है, जहां किसान कई दिनों से खाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जमुना कुशवाहा भी इसी संघर्ष का हिस्सा थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जमुना कुशवाहा पिछले तीन दिनों से बडोराघाट खाद वितरण केंद्र पर यूरिया खाद के लिए लाइन में लग रहे थे। खाद तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन इस प्रयास में उनकी जान चली गई। किसान जमुना कुशवाहा यूरिया खाद प्राप्त करने की उम्मीद में रोज बड़ोराघाट खाद वितरण केंद्र पर जा रहे थे। वहां उन्हें खाद के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। सोमवार को भी वह खाद लेने की आशा में बिना कुछ खाए सुबह से ही लाइन में लग गए थे। कुछ देर लाइन में खड़े रहने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर वह जमीन पर गिर पड़े। इस घटना के बाद तहसीलदार और पटवारी ने उन्हें सरकारी गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही जमुना कुशवाहा ने दम तोड़ दिया।

तहसीलदार ने भाई को दी जानकारी- मृतक के छोटे भाई ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके भाई की मौत खाद की लाइन में लगने से तबीयत बिगड़ने के कारण हुई है। उन्होंने बताया कि तहसीलदार ने उन्हें फोन पर सूचित किया था कि उनके भाई की तबीयत लाइन में लगे होने के कारण दोपहर 12 बजे बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

आईएएस वर्मा बोले-कितनों को मारोगे, हर घर से संतोष निकलेगा

भोपाल (नप्र)। आईएएस अधिकारी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ (अजाक्स) के अध्यक्ष संतोष वर्मा का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे कहते दिख रहे हैं- कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने को जलाओगे, कितने को निगल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से निकलेगा, तो आपके पास इतनी ताकत नहीं कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको।

इस वाक्य के आगे संतोष वर्मा ने और क्या कहा, वीडियो में यह शामिल नहीं है। वीडियो कब और कहां का है, इसका पता भी नहीं चल सका है।

मीडिया ने जब इस बारे में आईएएस संतोष वर्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बात उनसे फोन पर उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर रावण ने कही थी। वे तो अजाक्स भवन में संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से इस बारे में बात कर रहे थे। वर्मा ने अपनी बात की शुरुआत इससे की थी कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण ने ये बात कही है कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे।

वर्मा ने कहा- जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, वह आपसी बैठक का है। यह संघ की बैठक से संबंधित है। इसमें कुछ गलत नहीं कहा है। जो बयान है, वह किसी और ने कहा है इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है।

ब्राह्मण समाज ने कहा- कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतरेंगे- वर्मा के इस नए वीडियो के वायरल होने के बाद ब्राह्मण संगठन ने नाराजगी जाहिर की है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के नेता पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा- ब्राह्मण बेटियों को लेकर अनर्गल बयान देने पर सरकार ने अब तक वर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। अगर जल्द ही उन पर एफआईआर और कार्रवाई नहीं हुई तो ब्राह्मण समाज सड़क पर उतरने पर मजबूर हो जाएगा।

मिश्रा ने कहा- वर्मा को कहां से ऊर्जा मिल रही है? उस पर नजर-ए-इनायत क्यों है? गेंद मुख्यमंत्री के पाले में है। उनसे आग्रह है कि इस मामले में जल्द कार्रवाई करें।

सरकार ने नहीं माना अजाक्स का अध्यक्ष- उधर, मध्य प्रदेश सरकार ने संतोष वर्मा को अजाक्स का अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया है। सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जानकारी दी है कि संघ के अध्यक्ष वर्मा नहीं, मुकेश मौर्य हैं। विधायक राजेंद्र भारती ने विधानसभा में इससे संबंधित सवाल लगाया था। 2 दिसंबर को यह जबाव सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से दिया गया।

गांजा तस्कर भाई से एमपी की मंत्री प्रतिमा बागरी ने झाड़ा पल्ला

बोलीं- कोई भी अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, भाई-बहनोई दोनों जेल में हैं

भोपाल (नप्र)। गांजे की तस्करी के मामले में गिरफ्तार भाई अनिल बागरी से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री प्रतिमा बागरी ने पल्ला झाड़ लिया है। भाई की गिरफ्तारी के अगले दिन मंगलवार को खजुराहो में मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा- कोई भी अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है। मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर लें। तथ्यों की जानकारी के बाद ही बात करें।

दरअसल, सोमवार को सतना की रामपुर बघेलान पुलिस ने अनिल बागरी को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। अनिल और उसके साथी पंकज सिंह से 46 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है।

19 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

इस बारे में एडिशनल एसपी प्रेमलाल धुर्वे ने कहा था- मुखबिर की सूचना पर 7-8 दिसंबर की दरमियानी रात रामपुर बघेलान पुलिस ने मरौहा गांव में पंकज सिंह के घर पर दबिश दी। घर के बाहर टीन शेड में धान की बोरियों के नीचे 4 बोरियां मिलीं। इनमें 48 पैकेट गांजा के बरामद किए गए। इसकी बाजार में कीमत 9 लाख 22 हजार 680

रुपए है।

आरोपी पंकज को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बरामद गांजा अनिल बागरी और उसके बहनोई शैलेन्द्र सिंह का बताया। पुलिस ने सोमवार को अनिल बागरी को भी गिरफ्तार कर लिया। एनडीपीएस एक्ट की विशेष कोर्ट में न्यायाधीश शशिकांत वर्मा के सामने दोनों आरोपियों को पेश किया गया था।

यहां से उन्हें 19 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इससे पहले 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस ने राज्यमंत्री बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह को भी इसी आरोप में गिरफ्तार किया था।

सवाल पूछने पर झल्ला गईं थीं मंत्री- सोमवार देर शाम खजुराहो के महाराजा कन्वेंशन सेंटर से निकलते समय मीडिया ने जब राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी से उनके भाई की गिरफ्तारी पर सवाल किया तो वे झल्लाती नजर आई थीं। वे बोली थीं- फालतू की बात करते हो आप लोग। वहीं, इस मामले में उनके पिता जय प्रताप बागरी ने फोन पर कहा था- मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है, अभी मैं बात नहीं कर सकता।

दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार- सतना पुलिस के मुताबिक, अनिल बागरी पिता जय प्रताप बागरी, निवासी भरहुत नगर हरदुआ और पंकज सिंह पिता सतेंद्र सिंह, निवासी मतहा को गांजा तस्करी करते रंगे हाथ पकड़ा गया है। मामले का एक अन्य आरोपी शैलेन्द्र सिंह पिता सुरेंद्र सिंह, निवासी विराट नगर फरार है। शैलेन्द्र, अनिल बागरी का बहनोई है। बता दें कि शैलेन्द्र सिंह बांदा जेल में बंद है। उसे बीते 3 दिसंबर को बांदा पुलिस ने गांजा तस्करी करते पकड़ा था।